

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंक: अक्तूबर-दिसम्बर 2015

दिल्ली

दिल्ली

दली

यमुना सफ़ाई

कार-फ़्री डे

शिक्षा-लोन

दिल्ली की शिक्षा नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन

प्राइवेट स्कूलों को एकाउंट की वैरिफिकेशन

जहाँ कई प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं वहीं कुछ प्राइवेट स्कूलों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने एकाउंट में हेर-फेर करते हैं। इसका सीधा नुकसान जनता को होता है जिन्हें ज्यादा फीस देनी पड़ती है।

इसीलिए यह तय किया गया है कि दिल्ली सरकार हर वर्ष हर स्कूल के एकाउंट की वैरिफिकेशन, सरकार द्वारा नियुक्त, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से करवाएगी। वह चार्टर्ड एकाउंटेंट केवल यह जांच करेगा कि कहीं उस स्कूल में फर्जी बिल लगाकर पैसों का गबन तो नहीं किया जा रहा है? कहीं उस स्कूल के बच्चों से फीस लेकर उस पैसे को स्कूल के बाहर अन्य गतिविधियों पर खर्च तो नहीं किया जा रहा?

कोई भी स्कूल शिक्षा के लिए क्या गतिविधियाँ कराता है और उन पर कितना पैसा खर्च करता है- उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर स्कूल का मैनेजमेंट अपने स्कूल में अपने तरीके से गतिविधियाँ कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। सरकार का मकसद केवल एक ही है- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों से जो फीस ली जा रही है, वह उन्हीं के ऊपर खर्च की जाए।

आठवीं क्लास तक बच्चों को पास करने की प्रणाली पर पुनर्विचार

वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून पास किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आए हैं। कई स्कूलों में देखने को मिला है कि पढ़ाई के स्तर में भारी गिरावट हुई है। चूँकि सभी बच्चों को पास करते जा रहे हैं, अध्यापकों की जवाबदेही खत्म हो गई है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। 8वीं क्लास तक सबको पास करते जाते हैं। जब वे बच्चे 9वीं क्लास में जाते हैं तो 9वीं क्लास में वे फेल हो जाते हैं। 9वीं क्लास के नतीजे बहुत खराब आए हैं। पिछले वर्ष 9वीं क्लास में लगभग 43% प्रतिशत बच्चे फेल हो गए। इन बच्चों और उनके माँ-बाप पर क्या गुजरी, यह आप समझ सकते हैं। 9वीं क्लास के इन बच्चों में कई बच्चों को तो बेसिक गणित एवं भाषा की भी जानकारी नहीं है। मैं कई अभिभावकों से मिला और लगभग सभी का मानना है कि हर क्लास में परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन्हें वापस एक साल उसी क्लास में बैठना चाहिए।

नर्सरी एडमिशन में धाँपलियाँ

हम सब जानते हैं कि नर्सरी के एडमिशन में कितनी धाँपलियाँ होती हैं। जायज-नाजायज पैसे लिए जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चों और उनके माता-पिता का इंटरव्यू लिया जाता है। अब कानून बदलकर इन सब गतिविधियों को रोक दिया जाएगा। अब एडमिशन के वक्त किसी किस्म के डोनेशन की अनुमति नहीं होगी। बच्चों और उनके अभिभावकों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप सब लोगों से सुझाव लेकर दाखिले की प्रक्रिया को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

टीचर्स की सैलरी

अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बराबर वेतन दिया जाएगा। इस प्रावधान से कुछ विसंगतियाँ पैदा हो गयी थीं।

दिल्ली में कई तरह के स्कूल हैं जो समाज के अलग-अलग तबके के बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ एक ओर कुछ स्कूल 500 रुपये महीने से भी कम फीस लेते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य स्कूल 10,000/- रुपये महीने तक की फीस भी लेते हैं। जाहिर बात है कि यह सभी स्कूल अपने टीचर्स को एक जितनी तनखाह नहीं दे सकते।

सरकारी स्कूलों में एक सामान्य टीचर औसतन लगभग 40-50 हजार रुपये महीना वेतन पाता है। अधिक फीस लेने वाले स्कूलों के लिए यह सैलरी देना आसान है लेकिन 500 रुपये महीना फीस लेने वाले स्कूलों के लिए यह तनखाह देना नामुमकिन है।

मैं आपको एक क्लास का उदाहरण देता हूँ। एक क्लास में लगभग 50 बच्चे पढ़ते हैं। हर बच्चे से अगर 500 रुपये महीना फीस ली जाती है, तो पूरी क्लास से महीने में 25 हजार रुपये आये। तो आप खुद ही सोचिए कि वो स्कूल उस क्लास को पढ़ाने वाले टीचर को 40 हजार रुपये तनखाह कैसे देगी? पर चूँकि अभी तक कानून में यह लिखा था कि हर प्राइवेट स्कूल को सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बराबर तनखाह देनी होगी, इसीलिए मजबूरन यह स्कूल अभी तक सभी टीचर्स से कागज पर फर्जी साइन करवाता था कि उन्हें 40 हजार रुपये महीना तनखाह दे दी गई है। लेकिन हकीकत में यह स्कूल अपने टीचर्स को कौन से केवल 5000 से 8000 रुपये महीना ही देता था। इस स्कूल के टीचर जब भी सरकार के पास शिकायत करने आते थे तो सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। क्योंकि सरकार यदि स्कूल को सरकारी टीचर के बराबर तनखाह देने के लिए बाध्य करती, तो यह स्कूल ही बन्द हो जाता। नतीजतन जब-जब इस स्कूल के खिलाफ शिकायतें आती थीं, तो उन शिकायतों को बन्द करने के लिए दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी इस स्कूल से रिश्ता लेकर आ जाता था और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।

क्या यह सिस्टम ठीक है? हम इसी सिस्टम को बदलना चाहते हैं। दिल्ली में 1000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं। इन स्कूलों में हर महीने 1000 रुपये से भी कम फीस ली जाती है। अगर इन स्कूलों को सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बराबर सैलरी देने के लिए बाध्य किया गया तो दिल्ली के यह 1000 स्कूल बन्द हो जाएंगे। कोई भी जिम्मेदार सरकार यह नहीं होने दे सकती। दूसरी ओर इन स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स का पूरी तरह से शोषण हो रहा है। उन्हें आज न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा। ऐसे टीचर्स को कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिलवाना ही चाहिए।

तो जहाँ एक ओर सरकार उन टीचर्स को कम से कम न्यूनतम वेतन दिलवाएगी जिन्हें आज न्यूनतम वेतन से भी कम पैसे दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार उन टीचर्स के वेतन को कम नहीं होने देगी जिन्हें सरकारी स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स के बराबर अथवा उनसे अधिक वेतन मिल रहा है।

यह कैसे होगा? अभी तक कानून में लिखा था कि हर प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को सरकारी स्कूलों के बराबर वेतन देगा। इस प्रावधान को हटाकर अब कानून में यह प्रावधान लाया जा रहा है कि हर प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को उतना वेतन देगा जितना सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट किया जाएगा। कानून में ये बदलाव करने के बाद सरकार एक कमेटी गठित करेगी जो सबकी राय लेकर सरकार को सुझाव देगी कि अधिसूचना में किस तरह के निर्देशन दिये जायें। पर सैद्धांतिक रूप से इस अधिसूचना के जरिये निम्न बातें सुनिश्चित की जायेंगी :-

1. जिस टीचर को आज हकीकत में छोटे वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलती है, उसे कम नहीं होने दिया जायेगा। अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार यह लागू भी करायेगी।
2. जिन टीचर्स को न्यूनतम वेतन से कम तनखाह मिलती है उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन दिलवाया जायेगा।
3. जो स्कूल अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते रहे हैं उन स्कूलों को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कहा जाएगा।
4. स्कूल फंड का एक निर्धारित प्रतिशत हर स्कूल को टीचर्स की सैलरी पर खर्च करना अनिवार्य होगा।

अलग-अलग फीस लेने वाले स्कूलों के लिए अलग-अलग सैलरी के स्लैब बनाए जाएँ- इस किस्म के सुझाव भी सरकार के पास आ रहे हैं। इन सभी सुझावों पर गौर करके अधिसूचना जारी की जाएगी।

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

दिल्ली

अंक : अक्तूबर-दिसम्बर 2015

प्रधान सम्पादक

सज्जन सिंह यादव

अतिरिक्त निदेशक

राजेश चोपड़ा

सम्पादक

डॉ. पंकज श्रीवास्तव

सम्पादकीय सहयोग

नलिन चौहान

कंचन आजाद, विनोद गुप्ता

चन्दन कुमार, अमित कुमार

मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र

सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

“दिल्ली” पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता

प्रधान सम्पादक

दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय

दिल्ली सरकार

खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दूरभाष : 23819046, 23817926

फैक्स : 23814081

ई-मेल : delhidip@gmail.com



आओ अब बस करें



10 लाख तक का शिक्षा लोन

इस अंक में...

हिन्दी

दिल्ली जनलोकपाल बिल-2015 पास	3
स्कूलों के बदले रंग-ढंग पर बच्चों ने लगाई मुहर	4
दिल्ली को पहले ही साल 245 नये स्कूलों को तोहफा	6
दिल्ली में खुलेगी 'स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी'	9
मोहल्ला क्लिनिक-सेहत का एटीएम	11
इन्द्रधनुष की सुरक्षा में दिल्ली के बच्चे	13
दिल्ली में खत्म हुआ 'रेड राज'	18
शुरू हुई 'स्वच्छ यमुना' के संकल्प की आरती	21
ऐफिडेविट समाप्त	24
मंत्री को बरखास्त किया केजरीवाल ने	25
श्रद्धांजलि	27
गोरक्षा पर महात्मा गांधी की राय	28

पंजाबी

ਦਿੱਲੀ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ-2015 ਪਾਸ	1
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 245 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ !	2
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਏਟੀਐਮ	3
ਆਰੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ	5
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 'ਰੇਡ ਰਾਜ'	8
ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਮਾਪਤ	11
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ	12
ਗਾਊਂ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ	14

उर्दू

1.....	دہلی جن لوک پال بل 2015 پاس
2.....	دہلی کو پہلے ہی سال 245 نئے اسکولوں کا تحفہ
3.....	محله کلینک صحت کا اے ٹی ایم
5.....	دہلی کو بچانا ہے تو آب بس کریں
8.....	دہلی میں ختم ہوا ریڈ راج
11.....	ایفی ڈیوٹ ختم
12.....	گائے کی حفاظت پر مہاتما گاندھی کی رائے
13.....	گہرے الزام پر اپنے ہی وزیر کو برخاست کیا کجریوال نے



संविधान दिवस

26 नवंबर

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक [संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
बी-ब्लॉक, विकास भवन, द्वितीय तल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-02

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

दिल्ली जनलोकपाल बिल-2015 पास



अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए जनलोकपाल बिल पास कर दिया। इस बिल के दायरे में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी रखा गया है। इस बिल का नाम दिल्ली जनलोकपाल बिल-2015 है।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जोरदार अन्ना आंदोलन की यह मुख्य मांग थी जिसे दिल्ली की जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया था। इसी आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था जिसने सत्ता में आने पर जनलोकपाल बिल पास करने का वादा किया था। पिछली बार इस बिल को पेश करने से रोके जाने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया था। दोबारा जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता संभालते ही उन्होंने जनलोकपाल कानून बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी थी।

इस बिल के तहत किसी भी जांच को 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। ट्रायल भी छह महीने के तय वक्त में

पूरे करने होंगे। यानी साल भर में मामले को अंजाम तक पहुंचाना इस बिल की अनिवार्य शर्त हैं। 18 नवंबर को दिल्ली सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसका स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा—

“दिल्ली के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। दिल्ली कैबिनेट ने जनलोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। उन सभी को बधाई जिन्होंने इसके लिए दिन-रात मेहनत की।”

दिल्ली जन लोकपाल बिल में करप्शन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। आरोप साबित होने पर प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रावधान भी इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट भी पर्याप्त संख्या में हो। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट होंगे तो निश्चित समय-सीमा में ट्रायल पूरा हो सकेगा। ■



स्कूलों के बदले रंग-ढंग पर बच्चों ने लगाई मुहर

मॉडल स्कूलों में दिखे बदलाव से खुश हुए बच्चे और अभिभावक

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई मुहिम रंग दिखाने लगी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी भी मायने में निजी स्कूलों से कमतर नहीं होंगे और यह बात अभिभावक भी मानने लगे हैं कि सरकार के प्रयास का असर उनके बच्चों की समझदारी में साफ दिखाई पड़ रहा है।

आम आदमी पार्टी की सरकार को विरासत में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी जरूरतों का अभाव झेल रही

स्कूली व्यवस्था मिली थी। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देशन में हालात सुधारने के लिए एक पायलट योजना बनाई गई। इसके तहत 54 स्कूलों का चयन किया गया। इन स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की ट्रेनिंग पर खास जोर देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा भी दुरुस्त करने की कोशिश की गई। एक सर्वे के नतीजे बताते हैं कि इस योजना का शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों पर सकारात्मक असर पड़ा है।

सरकार ने "पायलट स्कूलों" के लिए कई स्तरों पर योजना बनाई थी। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए

अलग-अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग में नेतृत्व क्षमता के विकास पर खास जोर दिया गया क्योंकि इसके बिना किसी स्कूल को आगे ले जाना असंभव है। शिक्षकों की समस्याओं को समझा गया और उन्हें बताया गया कि वे विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे गैरसरकारी संगठन 'प्रथम' ने एक सर्वेक्षण के जरिये पता लगाया कि विद्यार्थियों को अपना विषय कितना समझ में आता है। इसके लिए तीसरी से पाँचवीं और छठीं से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक टेस्ट आयोजित किया गया। पता यह चला कि आठवीं के बच्चों को भी अपने विषय के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं होती।

इन नतीजों के आधार पर विद्यार्थियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बाँटकर उनकी जरूरतों के हिसाब से पढ़ाया गया। पढ़ने-पढ़ाने का अंदाज बदला तो विद्यार्थियों की

दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास हुआ और कक्षाएँ सही मायने में ज्ञान अर्जित करने के केंद्र में बदल गईं। इमारतों, फर्नीचरों और शौचालयों की टूट-फूट भी दूर की गई।

इस प्रयास का नतीजा जानने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक सर्वेक्षण कराया गया। सभी 54 स्कूलों के 20-20 छात्रों का चयन किया गया जिनसे फोन पर सवाल करके बदलाव की सूरत जानने की कोशिश की गई। करीब एक हजार बच्चों से फोन पर बात करने पर पता चला कि स्कूलों में जमीन-आसमान का अंतर नजर आ रहा है। नतीजे से उत्साहित सरकार ने अब तय किया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों को इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि अगले सत्र से दिल्ली के सभी एक हजार से ज्यादा स्कूलों में यह योजना लागू कर दी जाएगी। सरकार जल्द से जल्द उस लक्ष्य को पाना चाहती है जिसमें कहा गया है कि गुणवत्ता के लिहाज से दिल्ली के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर साबित होंगे। ■

81 फीसदी बच्चों को अच्छे लगने लगे टीचर जी !

- ▶ 89 फीसदी छात्रों ने माना कि उन्हें अपने स्कूल के मॉडल स्कूल होने की जानकारी है।
- ▶ 82 फीसदी ने कहा कि उनका स्कूल अब साफ-सुथरा है। 84 फीसदी ने कहा कि यह सफाई पिछले दो-तीन महीने में बढ़ी है
- ▶ 69 फीसदी ने कहा कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी आसानी से मिल रहा है। 64 फीसदी ने कहा कि पानी की गुणवत्ता सुधरी है।
- ▶ 66 फीसदी ने कहा कि स्कूल के शौचालय साफ हैं और 68 फीसदी ने कहा कि पिछले दो-तीन महीने में सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है।
- ▶ 82 फीसदी ने कहा है कि प्रधानाचार्यों का स्वैया सकारात्मक हुआ है
- ▶ 81 फीसदी ने माना है कि शिक्षकों का व्यवहार बेहतर हुआ है।
- ▶ 75 फीसदी ने माना कि शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका बदला है।

दिल्ली को पहले ही साल 245 नये स्कूलों का तोहफ़ा !

सरकार ने पांच साल में 500 स्कूल बनाने का वादा किया था

दिल्ली में स्कूली शिक्षा की हालत बदलने के लिए सरकार की कोशिशों का असर दिखने लगा है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने पर दिल्ली में पांच साल में 500 नये स्कूल बनाये जाएंगे लेकिन जिस रफ़्तार से सरकार ने काम किया है उससे लगता है कि एक साल में ही इसका आधा लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा जो एक मिसाल है।

दिल्ली में प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक कुल 1011 स्कूल हैं। 11 वीं और 12वीं के छात्रों की तादाद करीब तीन लाख से ऊपर है। जब नई सरकार ने कमान संभाली तो शिक्षक-छात्र अनुपात में भारी असंतुलन (एक क्लास में कहीं 174 तक छात्र थे) से लेकर लेकर कमरों की भारी कमी सामने थी। स्थिति बदलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू हुए। सरकार ने स्कूली शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए ठोस कार्यक्रम शुरू किये। इसके तहत कुल 25 स्कूल निर्माणाधीन हैं और अगले सत्र में भी बीस नये स्कूल बन जाएंगे।

शिक्षा मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष

सिसोदिया के मुताबिक मौजूदा स्कूलों में 8000 नये कमरे जोड़ने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगर एक स्कूल औसतन 40 कमरों का माना जाए तो मतलब यह हुआ कि दिल्ली में 200 नए स्कूल अगले साल तक बन जाएंगे। सरकार का पांच साल में पांच सौ स्कूल बनाने का वादा था। इस तरह सरकार पहले साल ही लक्ष्य के लगभग आधे स्कूल बना पाने में सफल होगी।

दिल्ली की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की राह में शिक्षकों की कमी एक भारी रोड़ा थी। इसे देखते हुए अगले सत्र से बीस हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इरादा यह है कि जल्द से जल्द 1:40 का आदर्श अनुपात हासिल किया जा सके। यानी एक शिक्षक पर चालीस से ज्यादा विद्यार्थियों की जिम्मेदारी न हो। ऐसा होने पर शिक्षक हर विद्यार्थी पर ध्यान दे पाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

इसके साथ ही स्कूलों में शौचालयों से लेकर प्रयोगशालाओं की कमियों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इरादा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल नया अनुभव हो। इन स्कूलों से पढ़कर निकलने वाले बच्चे किसी भी तरह निजी स्कूलों के बच्चे से कमतर न साबित हों।



दिल्ली सरकार का क्रांतिकारी कदम सरकार की गारंटी पर 10 लाख तक का शिक्षा लोन

पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर शुरू हुई शिक्षा लोन योजना

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के हाथों एजुकेशन लोन का चेक लेते हुए श्वेता सिंह की आँखें खुशी से चमक रही थीं। सरकार की गारंटी पर पंजाब नेशनल बैंक ने श्वेता के लिए एक लाख 37 हजार रुपये का एजुकेशन लोन मंजूर किया था। श्वेता, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थर्ड इयर की छात्रा है। हरिनगर निवासी श्वेता के इलेक्ट्रीशियन पिता ने पहले दो साल की फीस किस मुश्किल से जुटाई थी, यह वही जानती है। इसलिए 9 सितंबर 2015 की यह तारीख उसके लिए एक नई दुनिया के खुलने जैसा था, जहाँ राज्य सरकार ने अभिभावक की जगह ले ली थी।

यह सिर्फ श्वेता की कहानी नहीं है। दिल्ली से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले उन तमाम बच्चों की जिंदगी बदलने की कहानी है जो पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। या फिर बैंकों से शिक्षा लोन लेने के लिए माँ-बाप को घर गिरवी रखना पड़ता था। गिरवी घर के बच्चे किसी तरह पढ़ते तो थे, लेकिन सीने पर पहाड़ जैसा बोझ लिए। दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए इस स्थिति को बदलने की योजना लागू कर दी।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम के नाम से शुरू हुई इस उच्च शिक्षा कर्ज योजना के तहत जरूरतमंद



एजुकेशन लोन की खास बातें

- , t d'ku yku iku d fy, Nk=k dk fnYyh d Ldy l ckjgoh ikl gkuk t#jh gA
- ljdkjh depkfj;k vkj vQljka d cPp Hkh bl ;ktuk d rgr yku y ldr gA
- ftud ikl yku fLD;fjVh dk dkb l kku ;kuh lEifUk u gk
- ftud ikl dkb jktxkj uk gk
- ftUg f'k{kk d vHkko e ukdjh u fey jgh gk
- Nk= viuh fMxh vFkok dkl [kRe dju d ,d lky ckn l yku pdk ldr g] ;kuh mUg ,d lky rd dkb fQØ ugh djuh iMxhA
- ,d lky ckn EMI ;kuh fdLrk e yku pdk;k tk ldxkA
- yku pdku d fy, vfkdre 15 lky rd dk oä fn;k tk;ixkA
- vxj Nk= , t d'ku ihfj;M d nkjku gh yku pdkr g rk mUg 1% de C;kt nj l Hkxrku dh lfoëkk gkxhA , t d'ku yku fd l Hkh rjg d fMxh dkl vFkok fLdy MoyieV dkl d fy, fn;k tk,xkA
- bl , t d'ku yku Ldhe d rgr dkl Qh l fdrkc] ;fuQke] ykbcjh@y/c rFkk vU; lfoëkk, doj gA

छात्र-छात्राएं तमाम बैंकों से 10 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस योजना में किसी तीसरे पक्ष की गारंटी या मारजिन धनराशि की जरूरत नहीं होगी। कर्ज प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। लोन की गारंटी सरकार लेगी।

शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस योजना की शुरुआत के मौके पर इसे देश के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम बच्चे पैसे के अभाव में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते थे। यही नहीं, कई अभिभावकों के पास कर्ज के लिए गारंटी देने के पैसे नहीं होते थे और उन्हें लोन नहीं मिल पाता था। लेकिन दिल्ली सरकार की शिक्षा लोन योजना का लाभ लेने में ऐसी कोई बाधा नहीं होगी। दिल्ली सरकार इन बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनके लोन की गारंटी लेती है।

सरकार को पूरा भरोसा है कि ये बच्चे भविष्य में ना केवल लोन चुकता कर देंगे बल्कि समाज और देश के विकास में बड़ी भूमिका अदा करेंगे।

दिल्ली सरकार की इस अनोखी योजना के मताबिक बैंक के बेस रेट से 2% ऊपर की ब्याज दर पर ये लोन लिया जा सकेगा, जिसको 15 साल की ईएमआई में चुकाना होगा। डिग्री हासिल करने के एक साल बाद से लोन चुकाने की सुविधा होगी। ■





खेलेंगे-कूदेंगे बनेंगे नवाब ! दिल्ली में खुलेगी ‘स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी’

गली-कूचों से खोजी जाएगी खेल प्रतिभाएँ, विधानसभा स्तर पर होंगी प्रतियोगिताएँ

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में नई खेल संस्कृति विकसित करने का बीड़ा उठाया है। कोशिश की जा रही है कि वार्ड स्तर से लड़के-लड़कियों में खेलों के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाए ताकि प्रतिभाओं को वक्त रहते पहचान लिया जाए और उन्हें जरूरी सुविधाएं देकर तराशा जाए। यही नहीं आगे चलकर प्रतिभाशाली छात्रों को खेलों में ही डिग्री हासिल हो जाए ताकि उनके करियर की राह में बाधा न आये। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ‘स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी’ स्थापित करने की घोषणा की है।

आखिर यह अनोखा विचार आया कहां से ? पिछले दिनों पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डेल्ही स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके पीछे की कहानी बताई।

उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक लड़का उनसे मिलने आया। उसने बताया कि 12वीं के बाद उसने एथलेटिक्स पर ध्यान देना शुरू किया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं

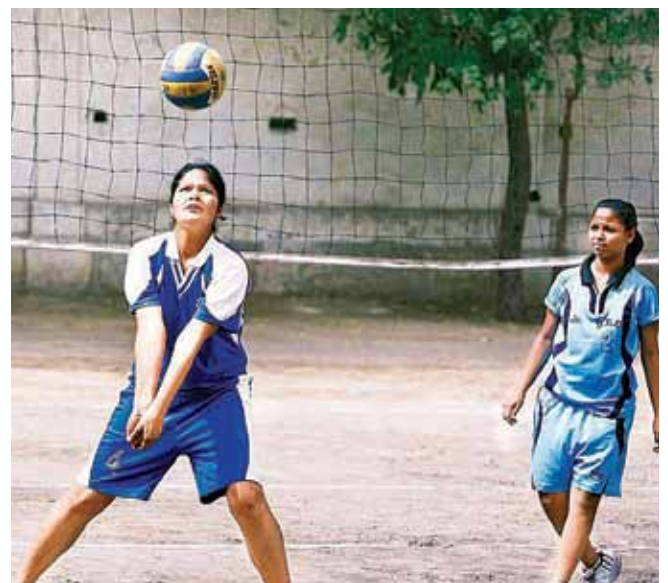


तक गया। लेकिन खेल पर पूरा ध्यान देने के कारण 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। अब जब वह किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उससे कहा जाता है कि वह ग्रेजुएट नहीं हैं। उस लड़के का दर्द था कि जिन लोगों ने तीन-चार साल फिजिक्स-कैमिस्ट्री को दिए वे ग्रेजुएट हो गए। उन्हें नौकरी मिल सकती है। जबकि उसने 12वीं के बाद खेल को चार साल दे दिए, जो किसी काम नहीं आ रहे हैं। अब वह क्या करे?

दिल्ली सरकार का खेल मंत्रालय भी संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार ऐसी ही समस्या को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी खोलने जा रही है जहाँ बाकी विषयों की तरह खेल पर फोकस करने वाले बच्चों को डिग्री दी जा सके। उन्होंने कहा कि, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच से सुशील पहलवान, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा जैसी प्रतिभाएं सामने आएँ और देश का नाम रोशन करें तो हमें कुछ नया सोचना होगा। स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी इसी दिशा में एक कदम है।

पटपड़गंज के ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक सप्ताह तक चली यह प्रतियोगिता शिक्षा विभाग

के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। इसमें तकरीबन 1,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जो वार्ड स्तर से चुन कर आये। सरकार की योजना है कि ऐसी प्रतियोगिताएं सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएं। विधानसभा प्रतियोगिताओं से निकली प्रतिभाओं को जिला स्तर पर और जिला स्तर से निकली प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर मौका दिया जाएगा। इससे गली-कूचों में छिपी दिल्ली की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। ■



मोहल्ला क्लीनिक ‘सेहत का एटीएम’



पहले मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। केजरीवाल सरकार अपने वादे के मुताबिक पूरी दिल्ली में एक साल के अंदर एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोल देगी। मतलब लोगों के मुहल्ले में इलाज और जांच की सुविधा। बीमारियों को पनपने से पहले ही पकड़ने और खत्म करने की दिशा में मोहल्ला क्लीनिक अहम भूमिका अदा करेंगे।

आखिर मोहल्ला क्लीनिक है क्या और इसमें नया क्या है? इसकी झलक पश्चिमी दिल्ली के पीरगढ़ी इलाके में खुले पहले मुहल्ला क्लीनिक से मिलती है। इस पूरी तरह वातानुकूलित क्लीनिक में डॉक्टर, नर्स के साथ फार्मसिस्ट और लैब टेक्नीशियन भी है और पचास से ज्यादा जांच की सुविधा। सिर्फ बीस लाख रुपये में बने इस क्लीनिक

को लोग फाइव स्टार क्लीनिक का नाम दे रहे हैं। यहाँ मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियाँ, पीने का साफ पानी और टेलिविजन भी है। गरीबों के लिए तो यह क्लीनिक एक नियामत की तरह है क्योंकि बीमार पड़ने पर उन्हें जिन जाँचों के लिए दर-दर भटकना पड़ता था वे अब उनके दरवाजे मुमकिन हैं। जाँच रिपोर्ट देखकर डॉक्टर जो दवा उन्हें लिखते हैं वह भी उन्हें इसी क्लीनिक से मिल जाती है।

दिल्ली के स्वास्थ्यमंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि पहले अनुमान था कि 80 फीसदी मरीजों को मुहल्ला क्लीनिक से राहत मिल जाएगी, सिर्फ 20 फीसदी को ही बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ेगा, लेकिन अनुभव बता रहा है कि मुहल्ला क्लीनिक में 95 फीसदी तक मरीजों का इलाज संभव है। अभी 50 तरह की जाँच की सुविधा को भविष्य



में 100 करने की योजना है। इससे मरीजों को जांच कराने, रिपोर्ट लेने और फिर उसे डाक्टर को दिखाने के क्रम में जो समय और धन खर्च करना पड़ता था, वह भी बच रहा है। यानी जब पूरी दिल्ली में एक हजार मुहल्ला क्लीनिक खुल जाएंगे तो फिर बड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नहीं दिखेगी। अभी कई अस्पतालों में रेलवे प्लेटफार्म जैसे दृश्य दिखते हैं। कई जगह एक बेड पर दो मरीज भी पड़े दिखते हैं। लेकिन मरीजों को शुरू में ही इलाज मिल जाएगा तो ज्यादातर मामलों में बीमारी बढ़ने ही नहीं पाएगी।

श्री जैन ने बताया कि मुहल्ला क्लीनिक में मरीजों को टोकन दे दिया जाएगा ताकि उन्हें अपनी बारी के आने के समय का अंदाजा हो जाए। अगले चरण में एक ऐप इस्तेमाल होगा जिससे लोगों को मोबाइल के जरिये एप्पॉइंटमेंट और अन्य सूचनाएँ मिल सकें।

दरअसल, दिल्ली सरकार की योजना दिल्ली को स्वास्थ्य का त्रिस्तरीय सुरक्षाचक्र मुहैया कराना है। पहले चरण में

मुहल्ला क्लीनिक, फिर पॉली क्लीनिक और फिर सुपर स्पेशियलिटी क्षमता वाले अस्पताल। उच्च स्तरीय जाँचों के लिए दिल्ली में सौ पॉली क्लीनिक भी खोले जाने हैं। ये मुहल्ला क्लीनिक और बड़े अस्पतालों के बीच लिंक का काम करेंगे। 9 नवंबर को गाँधीनगर के कांतिनगर में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले पॉली क्लीनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस मॉडल पॉलीक्लीनिक के कामकाज पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि जब सौ पॉलीक्लीनिक खुल जाएँ तो दिल्ली वालों को पूरा लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि आजादी के 68 सालों के बाद दिल्ली के अस्पतालों में महज 10 हजार बेड का इंतजाम है जिनमें इमरजेंसी के लिए बमुश्किल एक हजार हैं। अगले दो से ढाई साल के भीतर सरकार अस्पतालों में बेडों की संख्या को बढ़ाकर 20 हजार कर देगी जिसमें सात से आठ हजार इमरजेंसी और आईसीयू के लिए इस्तेमाल होंगे। साथ ही सरकार दिल्ली में 250 डेंटल क्लीनिक भी खोलने जा रही है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से दिल्ली को पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य जोन में बाँटा है। ये पाँचों क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे। यानी मुहल्ला क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का पूरा तंत्र हर क्षेत्र में मौजूद रहेगा। किसी को दूसरे क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी लोगों के समय और पैसे की बचत होगी। ■

दिल्लीवालों को मिलेंगे ‘हेल्थ कार्ड’

fnYyh di ykxk dh lgr ij [kk l è;ku nr; g, ljdkj gYFkdM ;ktuk ij dke dj jgh
gA bjknk vxy lky&M< lky e LokLF; lokvk dk v,uykbu djr; g, gj ukxfjd dk ,d
gYFkdM eg;k djuk gA bl dkM e ejht dh ubl vkj ijkuh chekfj; k dk ijk y[
tk[kk gkxkA ejht egYyk Dyhfud] i,yh Dyhfud vkj lij Lif'k;yVh
vLirkyk e budk bLreky dj ldxkA mli viuh tkp fjikV
ydj tku dh t:jr ugh iMxhA lHkh dN v,u ykbu
gkxk vkj bl ck;kefVd gYFkdM d tfj; MkDVj ejht
dh tkp fjikV vkj chekfj; k rFkk bLreky dh xbl nokvk
dk bfrgkl iyd >idr tku yxkA



इन्द्रधनुष की सुरक्षा में दिल्ली के बच्चे



दिल्ली में न किसी माँ का आँचल सूना हो न किसी घर का आंगन। बच्चों पर न पड़े किसी बीमारी का साया। हर संकट से रहें सुरक्षित। इस लक्ष्य को पाने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है "मिशन इन्द्रधनुष"।

यह 'इंद्रधनुष' दिल्ली के लाखों बच्चों को रोगों से बचाएगा भी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करके बीमारियों से लड़ने में मदद भी करेगा। यह दरअसल स्वास्थ्य विभाग का महात्वाकांक्षी टीकाकरण कार्यक्रम है जिसका मकसद बच्चों को सात आवश्यक टीकों का सुरक्षा कवच मुहैया कराना है।

दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचलित मिशन इन्द्रधनुष कवच प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल

ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजधानी के झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति में सुधार करना और टीकाकरण कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाना है। लक्ष्य



दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित मिशन इन्द्रधनुष कवच प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजधानी के झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति में सुधार करना और टीकाकरण कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाना है। लक्ष्य यह है कि 2019 तक 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये।

यह है कि 2019 तक 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये।

इस मिशन को 'इंद्रधनुष' नाम दिया गया। जिस तरह इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, वैसे ही सात तरह के टीके, सात जानलेवा बिमारियों से बचायेंगे। इंद्रधनुष के निशाने पर हैं—

1. डिप्थीरिया,
2. काली खाँसी,
3. टिटेनस,
4. पोलियो,
5. टी.बी
6. मिसल्स,
7. हेपेटाइटिस-बी

'इंद्रधनुष' का पहला चरण काफी सफल रहा जिसके बाद दूसरा चरण शुरू किया गया है। चिन्हित बच्चों और गर्भवती माताओं का संपूर्ण टीकाकरण करके बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम की सतत् निगरानी के लिए सरकार ने सभी चिन्हित क्षेत्र के लिए हेल्थ मॉनिटर नियुक्त किये हैं जो कि मौके पर हालात देखकर सरकार को सीधे रिपोर्ट दे रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने इस 'मिशन इन्द्रधनुष कवच प्रतिरक्षण कार्यक्रम' को लोकप्रिय

बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से अपने बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए योजना का लाभ लेने के लिए अपील की गई। सरकार के जागरूकता अभियान का असर स्वास्थ्य केन्द्रों पर देखने को मिला। बड़ी तादाद में गर्भवती महिलाओं एवं नौनिहालों को मिशन इन्द्रधनुष कवच प्रतिरक्षण टीकाकरण का लाभ मिला।

मिशन इन्द्रधनुष कवच के तहत 1000 से अधिक टीकाकरण केन्द्रों को सरका र



की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी अस्पतालों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी यह सेवा उपलब्ध है। ■



दिल्ली को बचाना है तो

‘आओ अब बस करें!’

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार गहराती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है वाहनो से निकलने वाला खतरनाक धुआँ। मेट्रो के विस्तार के बावजूद सड़कों पर वाहनों का बोझ कम नहीं हुआ है। सीएनजी से जो राहत मिली थी उसे गाड़ियों की तेजी से बढ़ी तादाद ने बेकार कर दिया। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहनो का इस्तेमाल करें। साथ ही साइकिलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाये।

हालात की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार ने ‘आओ अब बस करें’ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पहला ‘कार-फ्री डे’ 22 अक्टूबर को मनाया गया जब लालकिले से लेकर इंडिया गेट के बीच एक निश्चित रास्ते पर कारों या अन्य वाहनो के चलने पर पाबंदी थी।

इस रास्ते पर लोगों ने साइकिल रैली निकाली जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए।

केजरीवाल ने लालकिले से भगवान दास मार्ग तक साइकिल चलाई और प्रतिभागियों से अपील की कि वे साइकिल चलाने को एक आदत बनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में साइकिल चलाने की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मधुमेह से पीड़ित हैं और साइकिल चलाने से उनके स्वास्थ्य को लाभ होता है। उन्होंने लोगों से दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने की अपील की और कहा कि उनकी सरकार इन्हें फिर से डिजाइन करने की परियोजना पर काम कर रही है।



परिवहन मंत्री गोपाल राय के मुताबिक अब हर महीने की 22 तारीख को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 'कार-फ्री डे' मनाया जाएगा और अगले साल 22 सितंबर को पूरी दिल्ली 'कार-फ्री डे' मनाएगी। इस दिन विश्व स्तर पर 'कार-फ्री डे' का आयोजन होता है। नतीजे बताते हैं कि जिस रास्ते पर 'कार-फ्री डे' मनाया जाता है, वहां प्रदूषण में काफी कमी आती है।

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लगभग 90 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में पड़ोसी राज्यों से भी वाहनों का आना-जाना होता है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कुल मिलाकर जितनी गाड़ियाँ हैं, उससे ज्यादा अकेले दिल्ली में हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में जो हानिकारक तत्व हैं वह पर्यावरण सुधार की हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। साथ ही, चौराहे-चौराहे जाम लगा रहता है जो प्रदूषण की स्थिति को और भयावह बना देता है।

परिवहन मंत्री गोपाल राय हाल ही में एक अध्ययन कार्यक्रम के तहत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम गये थे। यह शहर पर्यावरण की बरबादी और फिर आये सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपाल राय के मुताबिक 1960-70 के दशक में स्टॉकहोम की हालत भी कुछ-कुछ दिल्ली की तरह ही थी। डॉक्टरों ने इस शहर में रहना

खतरनाक घोषित कर दिया था। व्यापारी भी दूसरे शहरों में पलायन कर रहे थे। आखिरकार इसके खिलाफ जनता ने आवाज बुलंद की। पर्यावरण राजनीतिक दलों का मुद्दा बना। ग्रीन पार्टी अस्तित्व में आई और आज यह शहर युरोप के सबसे सुंदर शहरों में माना जाता है।

परिवहन मंत्री के मुताबिक ऐसे में दिल्ली की हालत सुधारने के लिए भी जन जागरण सबसे जरूरी है। तमाम लोगों के लिए कारें दिखावे का जरिया हैं। एक-एक घर में कई कारें हैं। इस मानसिकता को बदलने का जरूरत है। लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। जहां तक हो सके साइकिलों का इस्तेमाल करें तभी हालात बदल सकते हैं। "आओ अब बस करें" अभियान का यही मकसद है कि लोग हालात की गंभीरता को समझें और बस या दूसरे सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल में ज्यादा दिलचस्पी लें।

लेकिन क्या यह सब इतना आसान है ? क्या दिल्ली के लोगों को सुरक्षित और आरामदेह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है ? इन सवालों के जवाब में गोपाल राय सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उनके मुताबिक मेट्रो के तीसरे चरण के विस्तार का काम जोरों पर है। इसके अलावा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) और डीटीसी के तहत एक-एक हजार नई बसें खरीदी जा रही हैं। पांच नए डिपो बनाये जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि अच्छी एयरकंडीशंड बसें सड़कों पर चलें ताकि दिल्ली वालों को निजी वाहन से न चलने का अफसोस न हो।

परिवहन मंत्री के मुताबिक अगले साल तक 5000 नई बसों का बेड़ा दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को काफी बेहतर बना देगा। कोशिश होगी कि लोगों को अपने घर से गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर स्तर की सुविधा मिले। ई रिक्शा और फीडर बसों के जरिये मेट्रो तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था लोगों को आकर्षित करेगी।

गोपाल राय के मुताबिक अब तक 1300 बसों में मार्शल की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा इसी वित्त वर्ष में सिविल डिफेंस से 5000 और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की

‘कार-फ्री डे’ से प्रदूषण में 60 फीसदी कमी !

दिल्ली में जहां ‘कार फ्री-डे’ मनाया गया वहां प्रदूषण में 60 फीसदी की कमी आई। दिल्ली में 73 लाख वाहन रोजाना सड़कों पर उतरते हैं। अगर इन्हें एक दिन के लिए भी रोका गया तो 216 करोड़ लीटर ईंधन की बचत की जा सकती है। इतना ही नहीं 8.58 टन सूक्ष्म कण, 7.4 टन सल्फर डाई ऑक्साइड, 105.38 टन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड तथा 452.51 टन कार्बन मोनो ऑक्साइड को भी हवा में घुलने से रोका जा सकता है।

एक अरब से ज्यादा कारें दुनियाभर में हैं। हर कार प्रति किलोमीटर 48 ग्राम सूक्ष्म कण और 30 ग्राम सल्फर ऑक्साइड छोड़ती है। पूरी दुनिया में इस खतरे को महसूस किया जा रहा है। कोलंबिया के बोगोटा में 15 साल पहले शुरू हुआ ‘कार फ्री-डे’ अब दुनियाभर के शहरों में मनाया जाने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहन ही हैं। ऐसे में अगर इन वाहनों के पहिए एक दिन भी रोक दिए जाएं तो प्रदूषण में भारी कमी देखी जा सकती है।

सफलता के बाद सभी बसों में इसका विस्तार होगा। सुविधा और सुरक्षा के साथ दिल्ली के लोग आवागमन कर सकें, इसके लिए उनकी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

सरकार की तैयारियाँ पर्यावरण की स्थिति की गंभीरता का पता दे रही है। ऐसे में सवाल दिल्ली वालों से है कि वे कितनी ताकत से यह कहने को तैयार हैं—आओ अब बस करें! ■



दिल्ली में खत्म हुआ 'रेड राज'



- **वैट विभाग के बदले रंग**
- **भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी टैक्स व्यवस्था लागू**
- **व्यापारियों से उगाही हुई बीती ज़माने की बात**

वैट यानी 'वैल्यू एडेड टैक्स' या 'मूल्य संवर्धित कर'। व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में वसूले गये इस टैक्स से सरकार विकास के तमाम काम कराती है। लेकिन इस टैक्स को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच लगातार तनाव बना रहता था। वैट विभाग की ओर से आए दिन छापेमारी और अवैध वसूली की शिकायत व्यापारी करते थे तो दूसरी तरफ उन पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगता था। हर तरफ अविश्वास का वातावरण था।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार ने "रेड-राज" बंद करते हुए घोषणा की कि वह व्यापारियों पर पूरी तरह विश्वास करती है। यानी आये दिन व्यापारियों पर होने वाली औचक छापेमारी पूरी तरह बंद कर दी गई। व्यापारी अपने टैक्स का आकलन खुद करते हैं और रिटर्न को आनलाइन भरा जाता है। जिसे सरकार पूरी तरह स्वीकार करती है। साथ ही उनकी शिकायतों के निपटान के लिए पारदर्शी व्यवस्था कायम की गई। वैट के लिहाज से

दिल्ली में 105 वार्ड और 10 जोन हैं। दो जोन ऐसे भी हैं जो खास एक करोड़ से अधिक सालाना रिटर्न देते हैं। दिल्ली में करीब तीन लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं। जिन भी व्यापारियों का सालाना टर्नओवर है, उनका वैट विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

लेकिन सरकार व्यापारियों को राहत देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके तहत बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट का गठन किया गया है। इनमें वैट अधिकारियों के अलावा टैक्स विशेषज्ञ भी हैं जो विभाग में व्यापारियों से मिले आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो

संदिग्ध व्यापारी से जवाब-तलब किया जाता है। जरूरी होने पर सर्वे किया जाता है और सारी पूछताछ दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। इस सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है ताकि किसी तरह की अनियमितता या दबाव की शिकायत की गुंजाइश न रहे। साथ ही वैट कमिश्नर अंतिम समय पर तय करते हैं कि कौन-कौन से अधिकारी सर्वे करने के लिए संदिग्ध व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाएंगे। यानी किसी अधिकारी का तयशुदा क्षेत्र नहीं है। पहले की व्यवस्था में वैट कर्मचारियों के तय वार्ड या क्षेत्र होते थे और यह आरोप आम था कि वे व्यापारियों से नियमित उगाही करते हैं। नई सरकार ने वैट अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है

वैट डिपार्टमेंट ने करोल बाग की एक फर्म के करीब 50 करोड़ रुपये के महंगे इंपोर्टेड एलईडी टीवी सेट का स्टॉक जब्त किया। इन एलईडी को अवैध रूप से बेचा जा रहा था। एलईडी बेचने वाली फर्म अभी तक वैट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड भी नहीं थी।

वैट कमिश्नर एस. एस. यादव ने बताया चोरी पकड़ी गई है। टैक्स चोरी करने लाई जाएगी। इस फर्म के पास एलईडी आधार पर डिपार्टमेंट की टीम ने एरिया तौर-तरीकों को भी देखा। पूरी तैयारी के



वैट कमिश्नर ने बताया कि फर्म द्वारा किया गया था। जिस फर्म से एलईडी करोल बाग में अवैध रूप से इन टीवी सेटों डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि करोल एलईडी टीवी बेच रही है और कोई टैक्स

हासिल करने के बाद एनफोर्समेंट टीम ने फर्म पर छापा मारा। फर्म जी एस ओवरसीज के पास इन टीवी सेटों का विशाल स्टॉक पाया गया। कंपनी के मालिक ने अवैध रूप से टीवी बेचने की बात मान ली है। अधिकारियों ने लेन-देन से जुड़ी सभी जरूरी डॉक्युमेंट भी जब्त किए हैं।

वैट कमिश्नर के मुताबिक इस फर्म ने किसी भी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संस्था का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक होने पर उसे व्यापार एवं कर विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उसे एक टिन नंबर मिलता है और रिटर्न फाइल किया जाता है। डिपार्टमेंट ने DVAT अधिनियम 2004 के मुताबिक फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की गई है। इस ऑपरेशन में जॉइंट कमिश्नर रंजीत सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर विकास तोमर भी शामिल थे।

वैट कमिश्नर ने कहा है कि नियम-कायदों को मानने वालों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन टैक्स चोरों को बख्शा नहीं जाएगा।

कि 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स वालों के खिलाफ अभियान में और तेजी का विशाल स्टॉक पाया गया। सूचना के का सर्वे किया और फर्म के काम करने के बाद छापेमारी की गई।

एलईडी टीवी के पूरे स्टॉक को आयात टीवी का स्टॉक जब्त किया गया, वह की बिक्री कर रहा था। व्यापार एवं कर बाग की एक फर्म बड़े पैमाने पर आयातित नहीं दिया जा रहा है। सारी जानकारी

हासिल करने के बाद एनफोर्समेंट टीम ने फर्म पर छापा मारा। फर्म जी एस ओवरसीज के पास इन टीवी सेटों का विशाल स्टॉक पाया गया। कंपनी के मालिक ने अवैध रूप से टीवी बेचने की बात मान ली है। अधिकारियों ने लेन-देन से जुड़ी सभी जरूरी डॉक्युमेंट भी जब्त किए हैं।

बिल बनवाओ-इनाम पाओ

दिल्ली सरकार ने 'बिल बनवाओ- इनाम पाओ' नाम से नई योजना शुरू की है। योजना के तहत लोगों से अपील की गई है कि जो भी सामान खरीदें, उसकी पक्का बिल जरूर लें। सरकार ने इस बाबत 50 हजार रुपए तक का इनाम रखा है। इसके लिए खरीदी गई वस्तु की कीमत 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बिल की कॉपी को विभाग की वेबसाइट पर सात दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। प्रत्येक बिल के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा और एसएमएस के जरिए ग्राहक को भेज दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक महीने इनाम दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के दबाव से पक्की रसीद देने का दबाव दुकानदारों पर बढ़ेगा जिससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिल सकेगा।

कि वे व्यापारियों से पूरी विनम्रता से पूछताछ करें। उनके व्यवहार से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, इसका खास ध्यान रखा जाए।

नियम के तहत सौ रुपये से ज्यादा कीमत की वस्तु की बिक्री पर पक्की रसीद देना जरूरी है। लेकिन इस नियम का पालन न करने की शिकायत बड़े पैमाने पर है। ऐसे में उपभोक्ताओं को पक्की रसीदें लेने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए 'बिल बनवाओ-इनाम पाओ' योजना शुरू की गई है।

इसी के साथ दिल्ली में बाहर से आने और यहां से गुजरकर जाने वाले माल का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सुगम-2 फार्म की व्यवस्था की गई है। यह काफी सरल फार्म है। इससे केंद्रीय उत्पाद विभाग और आयकर विभाग को भी जोड़ने की

प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि यह पूरी तरह से स्पष्ट रहे कि व्यापारी ने कहाँ से माल मंगाया, कहाँ बेचा और कितना लाभ कमाया। अगर सबकुछ पारदर्शी हो जाए तो फिर वैट चोरी या विवाद की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ईमानदार व्यापारियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और सरकार को भी वैट चोरी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।

यही नहीं, सरकार ने एक इन्फार्मर स्कीम भी शुरू की है। इसके तहत वैट चोरी की सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और अगर सूचना की वजह से वैट वसूली हो पाई तो उचित इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही वैट अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने की भी योजना लाई जा रही है। ■





‘स्वच्छ यमुना’ के संकल्प की आरती

- ▶ शुरू हुई ‘यमुना आरती’
- ▶ यमुना जल की 24 घंटे होगी निगरानी
- ▶ गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के यमुना में नहीं डाला जाएगा
- ▶ 36 महीने में यमुना को नहाने लायक बनाना केजरीवाल सरकार का संकल्प

क्या बेजान होती जा रही यमुना में जान डालना संभव है? क्या दिल्ली फिर से यमुना की शान बन पाएगी? क्या यमुना तट का दिलकश नजारा दिल्ली वालों को उसी तरह अपनी ओर खींचेगा जैसा कि इतिहास की किताबों में दर्ज है? कल तक इन सवालों का जवाब देना मुश्किल था। लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना का हाल दुरुस्त करने को लेकर जिस तरह की प्रतिबद्धता जताई है, उससे इन सवालों का जवाब ‘हाँ’ में देना मुमकिन हुआ है।

13 नवंबर की शाम, अंतर्राज्यीय बस अड्डे के करीब कुदेसिया घाट पर हुई यमुना आरती सरकार के इसी संकल्प की बानगी थी। गीत-संगीत की सुमधुर लहरियों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यटनमंत्री कपिल मिश्र ने सैकड़ों लोगों के साथ जब बनारस की ‘गंगा-आरती’ तर्ज पर यमुना

आरती की तो दीयों की रोशनी में स्वच्छता का संकल्प जगमगा रहा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में यमुना की 24 घंटे निगरानी होगी जबकि अभी सिर्फ दिन में ही इस पर नजर रखी जाती है। सरकार की कोशिश है कि अगले एक-दो सालों में औद्योगिक या घरेलू सीवेज का एक बूंद भी बिना ट्रीटमेंट के यमुना में न जाने

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के साथ 50 फीसदी साझेदारी के साथ एक नई कंपनी बनाई गई है। पल्ला से ओखला तक फैली यमुना किनारे की सारी जमीन इस कंपनी को हस्तारित कर दी जाएगी ताकि विवाद समाप्त हो सकें। यह कंपनी पूरी तरह से यमुना की सफाई, पानी की उपलब्धता और तटों को विकसित करने की जिम्मेदारी संभालेगी।

दिल्ली में एसटीपी

दिल्ली में जनशोधन क्षमता बढ़कर 450 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) हो गई है, यानी 2250 मिलियन लीटर। एक मिलियन लीटर का मतलब 10 लाख लीटर होता है। दिल्ली जल बोर्ड का लक्ष्य 2015 के अंत तक जलशोधन क्षमता को बढ़ाकर 500 एमजीडी करना है। दिल्ली में फिलहाल 17 स्थानों पर 30 जलशोधन संयंत्र स्थापित हैं।

इस मौके पर पर्यटनमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्र ने अपना वादा दोहराया कि जन सहयोग से सिर्फ 36 महीने में यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाकर वे खुद इसमें स्नान करेंगे। यमुना सफाई सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए युद्धस्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

पूर्वी दिल्ली के गीता घाट पर अब हर रोज यमुना आरती हो रही है। जनजागरण के इस प्रतीक आयोजन से आम लोगों को जोड़ने के साथ-साथ इसे दिल्ली आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि वह हर हाल में अपना वादा पूरा करेगी।

यह 'यमुना स्वच्छता अभियान' दिल्ली के आधुनिक इतिहास का एक नया मोड़ साबित होगा। जल मंत्रालय का कामकाज संभालने के साथ ही कपिल मिश्र ने डीडीए, एसआईआईडीसी और दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों के साथ यमुना नदी का संयुक्त सर्वेक्षण किया था। वजीराबाद बैराज से लेकर आईटीओ पुल तक हुए इस सर्वेक्षण के दौरान कई जगहों से पानी का नमूना लिया गया। यमुना के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह 21 बड़े और सैकड़ों छोटे गंदे नालों का पानी है जो बिना शुद्ध किये यमुना में गिरता है। बहरहाल, सबसे ज्यादा प्रदूषित नजफगढ़ नाले को साफ करने का काम चल रहा है और बाकी के लिए भी वृहत योजना बनाई जा रही है।

वैसे, एक अच्छी खबर यह भी है कि यमुना का जो पानी दूर से पूरी तरह काला दिखता है, वह बाहर निकालने पर धूसर दिखता है। यमुना में जमा गाद इसकी बड़ी वजह है। सरकार सिल्ट सफाई को लेकर एक बड़ी योजना बना रही है जिसके बाद पानी के रंग में परिवर्तन आ जाएगा। ■

दिल्ली में यमुना सफाई-एक चुनौती

यमुना नदी का दिल्ली खंड इसके सर्वाधिक प्रदूषित खंडों में से एक है। यमुना एक्शन प्लान के दो चरण पूर्ण होने के बावजूद नदी की जल गुणवत्ता वांछित मानकों तक नहीं पहुंची है।

लगभग 224 किमी. की दूरी स्वच्छंद रूप से तय करने के बाद यमुना नदी पल्ला गांव के निकट दिल्ली में प्रवेश करती है और वजीराबाद में एक बार फिर से बैराज के माध्यम से घेर ली जाती है। यह बैराज दिल्ली के लिए पेयजल आपूर्ति करता है और यहां से आगे प्रवाह एक बार फिर से शून्य या बेहद कम हो जाता है। इसके बाद नदी में अनुपचारित या अंशतः उपचारित घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में मिलता है। एक बार फिर लगभग 25 किमी. बहने के बाद ओखला बैराज के आगे इसके पानी को आगरा नहर में सिंचाई के लिए डाल दिया जाता है और नदी एक बार फिर से ओखला बैराज में बंध कर रह जाती है। इसके कारण गर्मियों में बैराज से लगभग शून्य या बेहद नगण्य पानी निकलने दिया जाता है। ओखला बैराज के बाद नदी में पूर्वी दिल्ली, नोएडा और साहिबाबाद इलाकों से निकला घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट जल शाहदरा नाले के जरिए नदी में गिरता है। आखिर में यमुना में अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों का पानी मिलता है और लगभग 1370 किमी. चलने के बाद यह इलाहाबाद में गंगा से मिलती है।

दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है और दिल्ली खंड इस नदी का सबसे प्रदूषित खंड है। यमुना की सफाई के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन चरण में यमुना एक्शन प्लान बना लेकिन न तो प्रदूषण स्तर घटा और न ही नदी पर बढ़ता दबाव। शहर से नदी में गिरते अपशिष्ट जल के उपचार के लिए दिल्ली में स्थापित संयंत्रों की क्षमता का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। ऐसे में साफ-सुथरी यमुना का प्रवाह देखना अब भी एक स्वप्न भर है। यह बेसिन देश के बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। नदी पर पांच बैराजों की मौजूदगी के कारण पूरे वर्ष नदी की बहाव स्थितियों में काफी बदलाव देखा जाता है। अक्टूबर से जून तक नदी लगभग सूखी रहती है या कुछ खंडों में बहुत थोड़ा प्रवाह होता है जबकि मानसून अवधि (जुलाई-सितंबर) के दौरान इसमें बाढ़ आई रहती है। इस क्षेत्र की लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नदी के जल से होती है। ■



यमुना में नौका रेस

दिल्ली में यमुना का एक विहंगम स्वरूप वजीराबाद में दिखता है जब वह हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। यहां यमुना नदी के रूप में ही दिखती है न कि नाले के रूप में, जैसा कि दिल्ली की यमुना की शक्ल बना दी गई है। दुनिया को यमुना का यह स्वरूप दिखाने के लिए 23 अक्टूबर को यहां एक नौका रेस का आयोजन किया गया।

इस चौंपियनशिप में तमाम टीमों ने उत्साह से भाग लिया। देखने वालों को लगा कि वे केरल की मशहूर नौका प्रतियोगिता की झलक पा रहे हैं। गुब्बारों और खूबसूरत सजावट के बीच रंगबिरंगी नौकाओं को देखना रोमांचित कर रहा था। सरकार का इरादा पूरी दिल्ली में यमुना की ऐसी ही शक्ल देना है ताकि वजीराबाद में ही नहीं, आईटीओ पर भी लोग नौका विहार कर सकें। सरकार की कोशिशों और गंभीरता को देखते हुए लोगों को यकीन होने लगा है कि दिल्ली की चाँदनी रात में नौका विहार का सपना अगले कुछ सालों में हकीकत बन जाएगा। ■



एफिडेविट समाप्त

जनता की बात पर भरोसा न करके उससे हर बात के लिए शपथपत्र माँगा जाए, अब दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। लोगों पर पूरा विश्वास जताते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसले में अलग-अलग श्रेणियों के करीब 200 कामों के लिए हलफनामे (एफिडेविट) की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके बदले सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी होगा। साथ ही, कैबिनेट ने सेल्फ अटेस्टेशन को भी मंजूरी दे दी है। यानी लोग अपने प्रमाणपत्रों को खुद अटेस्ट कर सकेंगे। उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी के पास नहीं जाना होगा। 1 दिसंबर से लागू हुई इस व्यवस्था के जरिये दिल्ली सरकार ने जनता से किया गया अपना एक महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक 200 किस्म के कामों में एफिडेविट खत्म करने के फैसले का असर सरकार के ऐसे तमाम विभागों की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा जहां जनता को अक्सर परेशानी झेड़नी पड़ती है। सरकार ने तमाम विभागों से ऐसे शपथपत्रों की जानकारी मांगी थी जिन्हें जमा करना अनिवार्य तो था लेकिन यह महज औपचारिकता भर थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, समाज कल्याण विभाग, मातृ एवं शिशु कल्याण, एमसीडी, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जैसे विभागों में कोई शपथपत्र नहीं देना होगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब राशन कार्ड बनवाने और उसमें नाम जोड़ने या घटाने, ड्रुप्लीकेट राशन कार्ड, पते में बदलाव, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली लाडली स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, आय प्रमाणपत्र, ओबीसी एवं एससी एसटी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल 40 कामों में शपथपत्र की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस संख्या को और कम किया जाएगा। जहाँ बेहद जरूरी होगा वहीं शपथपत्र माँगा जाएगा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार झूठे सेल्फ डिक्लेरेशन देने वालों के प्रति लापरवाह रहेगी। ऐसा करने वालों को कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान किया जा रहा है।

f1Q lYQ fMDyji'ku l gkxk dke

- ,Meh'ku d le; fn, tku oky ,fQMfoV] MV v,Q cFk] Ldy l ?kj dh njh
- ukdjh dh 'k#vkr eı cek.ki=k dh lR;rk dı fy, fn, tku okyk 'kiFki=
- uke vkj lıue eı cnyko dı fy, fn; tku okyk 'kiFki=
- ırk cnyu
- jk'ku dkM cuoku vkj mleı t:jh cnyko djku
- VklQj v,Q ijfeV
- MlyhdV vkj-lh
- jxıy j Mkbfox ykblıl cuoku
- Mkbfox ykblıl dk fjU;oy
- bVju'kuy Mkbfox ijfeV
- fnYyh ykMyh Ldhe
- tUe ,oı eR;ı cek.ki= dı fjdkM eı djD'ku
- fuokl cek.ki=
- vk; cek.ki=
- vkchl hı , l l hı , l Vh cek.ki=
- u;k fctyh duD'ku dı le; fn; tku okyk 'kiFki=
- dE;fuVh lıVjı ckjkr?kj ;k ikdı cfdıx dı le; fn; tku okyk 'kiFki=

गंभीर आरोप पर अपने ही मंत्री को बरखास्त किया केजरीवाल ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग में एक ऐसी रेखा खींच दी है जो केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के लिए चुनौती बन गई है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर अपने ही एक मंत्री को बरखास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी।

बरखास्त किए गये मंत्री का नाम है आसिम अहमद खान। मटिया महल इलाके से विधायक आसिम अहमद खान के पास दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति के अलावा, पर्यावरण एवं वन, अल्पसंख्यक मामले

और इलेक्शन विभाग भी था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर से छह लाख रुपये रिश्वत मांगी। इस बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची उन्होंने मंत्री से सफाई मांगी और उन्हें बिना विलंब किए बरखास्त कर दिया गया। यही नहीं उन्होंने खुद प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को अपने इस कदम को जानकारी दी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कदम राजनीति में एक नई मिसाल मान जा रहा है। अभी तक राजनीतिक

दलों में आम सहमति है कि जब तक उनके किसी मंत्री या पदाधिकारी को अदालत पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा देती, तब तक उसे निर्दोष माना जाए। कई बार तो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद भी पद से हटाया नहीं जाता। जब मीडिया भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे

करता है, स्टिंग या दस्तावेज सार्वजनिक करता है, तो राजनीतिक दल उल्टा तथ्यों को तरोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाते हुए अदालत के फैसले के इंतजार की दुहाई देते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कदम बाकी राजनीतिक दलों को भी अपना रुख बदलने पर मजबूर करेगा।



आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से एक साफ-सुथरी सरकार देने का वादा किया था। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष के अरविंद केजरीवाल के वादे पर न सिर्फ यकीन किया, बल्कि खुलकर साथ भी दिया। यही वजह थी कि दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिया था।

ट्विटर पर कुछ प्रतिक्रियाएं

नवीन प्रकाश (दिल्ली)—काश सारे नेता अरविंद जी की तरह सच्चे और ईमानदार हो जाये। मेरा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलायेगा।

अमिताभ बोरठाकुर—(गुवाहाटी) यह असम के मुख्यमंत्री के लिए एक उदाहरण है। उन्हें भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए।

अभिषेक गौरव (पटना)—इसे कहते हैं सकारात्मक राजनीति।

करिसल अरुण (मुंबई)—हमें आप पर गर्व है अरविंद केजरीवाल।

राजेश तलवार (दिल्ली)—मुख्यमंत्री ने बहुत सही कदम उठाया। यह दूसरे राजनेताओं के लिए भी एक सबक है। आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं को सतर्कता से काम करना होगा।

नवाज मुहम्मद (कुवैत)—हमें अरविंद केजरीवाल पर फख्र है। भारत की आत्मा को बचाने के लिए आपको केंद्र में आना होगा।

श्रीनी पाल्थेपु (करीमनगर)—राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ आशा जगी है। नए विकल्प दिखने लगे हैं।

विवेक भारती (बेंगलुरु)—आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि वह भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है।

नंदन कोरंगा (दिल्ली)—मीडिया को केजरीवाल के अच्छे काम क्यों नहीं दिखते? ये बहुत गलत है। मीडिया ने दिल्ली सरकार का कोई भी एक अच्छा काम कभी भी नहीं दिखाया।

इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी। कई अधिकारी और कर्मचारी रिश्तत लेते रंगे हाथ पकड़े भी गए, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार के साथ अधिकारों का संघर्ष शुरू हो गयी। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को दिल्ली सरकार के अधिकारक्षेत्र से बाहर बता दिया। इसने दिल्ली सरकार के अभियान में बड़ी बाधा डाली।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने 9 अक्टूबर को आसिम अहमद खान को मंत्रिपद से बरखास्त करने के बाद 11 अक्टूबर को अपने आवास पर पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विधायकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने साफतौर पर कहा कि भ्रष्टाचार के साथ किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार के साथ-साथ पार्टी और उसके परिवार की भी बदनामी होगी। उन्होंने विधायकों के परिजनों से कहा कि उनकी पार्टी देश बदलने का एक अभियान है और अगर आपके घर का कोई शख्स विधायक या मंत्री है, तो उसकी शान को बनाये रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। देश को आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत आशाएं हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम राजनीति में क्यों आए हैं।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने भी भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले को सोचना चाहिए कि अगर वह जेल गया तो उसके बच्चों और परिवार के लोगों को समाज में क्या-क्या सुनना पड़ेगा। गलती एक आदमी करता है, लेकिन भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है। इस भावना को सभी को आत्मसात करना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल सरकार के इस रुख का दिल्ली की जनता पर बेहद सकारात्मक असर पड़ा। लोगों में संदेश गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के अपने वादे को भूले नहीं हैं और न ही मंत्रियों और विधायकों को भूलने दे रहे हैं। इसका सीधा फायदा जनता को होगा क्योंकि एक भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी शासन ही असल में सुशासन होता है। ■

साहित्य अकादमी से सम्मानित, हिंदी के वरिष्ठ कवि वीरेन डंगवाल का 28 सितंबर को बरेली में निधन हो गया। वे बीते सात-आठ सालों से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। गहन संवेदनाओं और जीवन की ऊष्मा से भरपूर कविताओं के लिए हिंदी जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले वीरेन जी की एक रचना के साथ उन्हें हमारी श्रद्धांजलि।

आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे

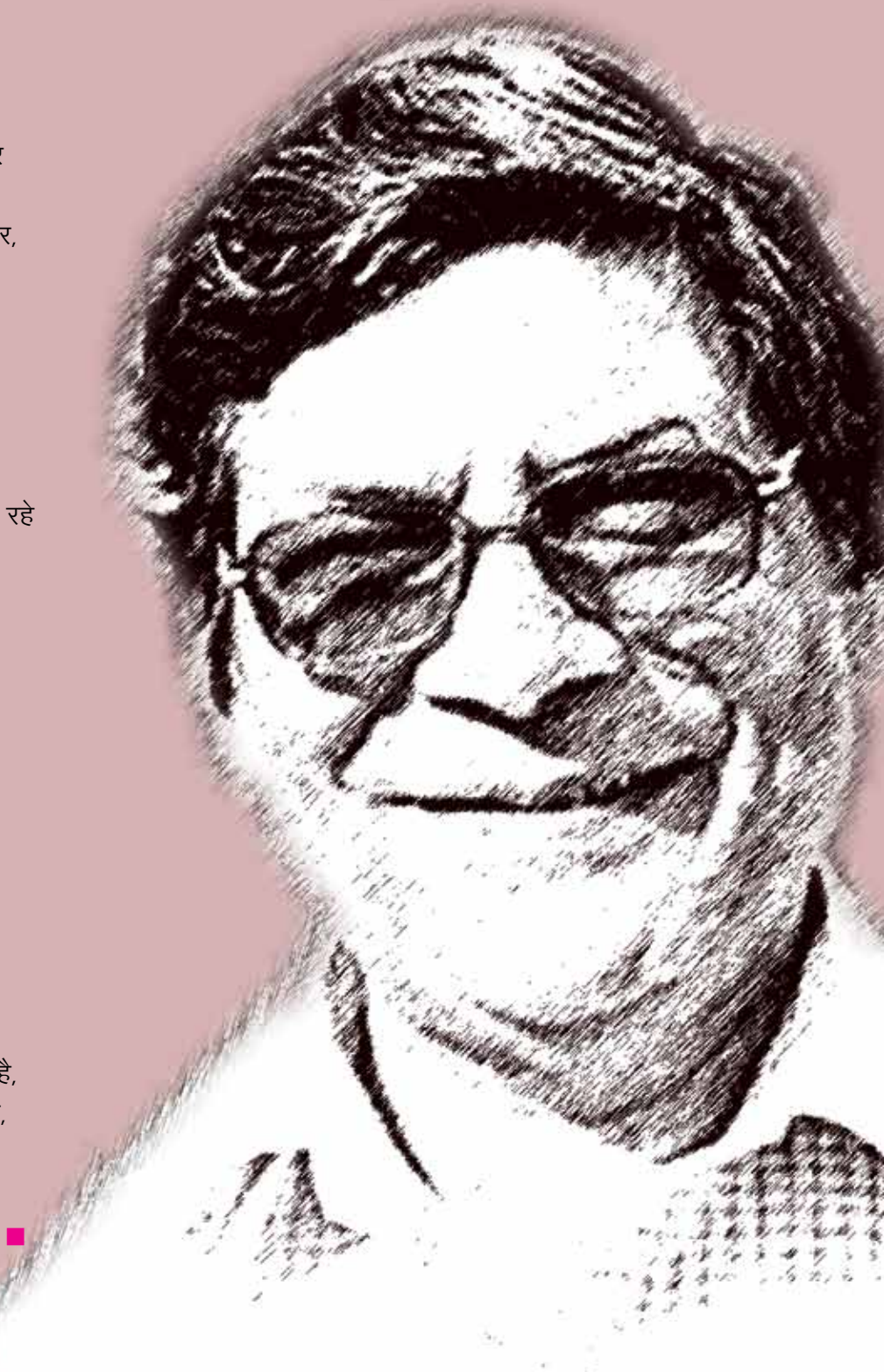
आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे

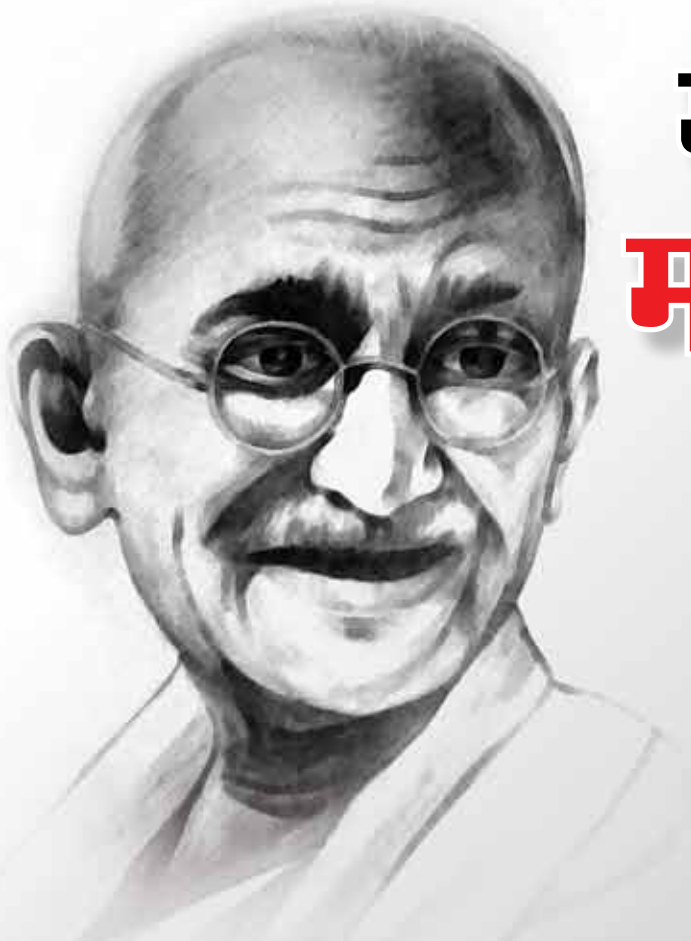
आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ़
है हवा कठिन, हड्डी-हड्डी को ठिठुराती
आकाश उगलता अंधकार, फिर एक बार
संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती,
होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार,
तब कहीं मेघ ये छिन्न-भिन्न हो पायेंगे
आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे.....

तहखानों से निकले मोटे-मोटे चूहे,
जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे
हैं कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें,
चीं-चीं-चिक-चिक की धूम मचाते घूम रहे
पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं
जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पायेंगे,
आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे.....

यह रक्तपात यह मारकाट जो मची हुई
लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है,
जो अड़ा हुआ है हमें डराता रस्ते पर,
लपटें लेता घनघोर आग का दरिया है,
सूखे चेहरे बच्चों के उनकी तरल हंसी
हम याद रखेंगे, पार उसे कर जायेंगे
आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे.....

मैं नहीं तसल्ली झूठ-मूठ की देता हूँ,
हर सपने के पीछे सच्चाई होती है,
हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है,
हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है,
आयें हैं जब चलकर इतने लाख वर्ष,
इसके आगे भी चलकर ही जायेंगे
आयेंगे, उजले दिन जरूर आयेंगे...





गोरक्षा पर महात्मा गांधी की राय

हां और नहीं के बीच हमेशा बैर रहता है. अगर मैं वाद-विवाद करूंगा तो मुसलमान भी वाद विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूंगा, तो वह भी टेढ़ा बनेगा।

अगर मैं बालिस्त भर नमूंगा तो वह हाथ भर नमेगा और अगर वह नहीं भी नमे तो मेरा नमना गलत नहीं कहलाएगा।

जब हमने ज़िद की तो गोकशी बढ़ी। मेरी राय है कि गोरक्षा प्रचारिणी सभा गोवध प्रचारिणी सभा मानी जानी चाहिए. ऐसी सभा का होना हमारे लिए बदनामी की बात है।

जब गाय की रक्षा करना हम भूल गए तब ऐसी सभा की जरूरत पड़ी होगी।

मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो उसके साथ मैं कैसा बरताव करूंगा? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पड़ना चाहिए तो मुसलमान भाई के पांव भी पड़ना चाहिए।

(‘हिंद स्वराज’ से)



मैं खुद गाय को पूजता हूं यानी मान देता हूं। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का, जो खेती प्रधान देश है, आधार है।

गाय कई तरह से उपयोगी जानवर है। वह उपयोगी जानवर है इसे मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे।

लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है वैसे ही मनुष्य भी फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है।

तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय दोनों का दुश्मन हो जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए।

अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं तो मानता हूं।

ਦਿੱਲੀ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ-2015 ਪਾਸ



ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਕੈਬੀਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ-2015 ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੁਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਯਲ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੈਅ ਵਕਤ

ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ-

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।''

ਦਿੱਲੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਯਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ■

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 245 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੌਹਫ਼ਾ !

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 500 ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12 ਤਕ ਕੁਲ 1011 ਸਕੂਲ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ 174 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 25 ਸਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਹ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8000 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ

ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ 40 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਭਾਰੀ ਰੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 1:40 ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚਾਲਯਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ■



ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਏਟੀਐਮ



ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਆਖਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਰਾਂਗੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣੇ

ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਇਕ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੰਦਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਭਵ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜੇ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 100



ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਰੀਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ। ਅਜੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬੈਠ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਪਵਾਈਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ

ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਟੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਚ ਪਧਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੌ ਪਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਂਤੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸੌ ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਖੁਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੋਂਦਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤ ਤੋਂ ਅਠ ਹਜ਼ਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 250 ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ, ਉਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮਧ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਖੇਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ■

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 'ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ'

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਥਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਾਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਥਕਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ।





ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਆਓ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਧੂੰਆਂ।

ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਓ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ 'ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ' 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਲਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮਾਰਗ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਦਾ ਬਣਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਨ ਜਾਗਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਆਓ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 'ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ' ਮਨਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ 'ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਵ ਹਨ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਰਾਹੇ-ਚੌਰਾਹੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਡਿਮਟਸ) ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ 5000 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਤਵਯ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਬਸਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਟਰੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਗਮ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 1300 ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ 5000 ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ !

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 73 ਲਖ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 216 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 8.58 ਟਨ ਸੂਫਮ ਕਣ, 7.4 ਟਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ, 105.38 ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ 452.51 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 48 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਫਮ ਕਣ ਅਤੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ’ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਾਹਨ ਹੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਏ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ-ਆਓ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ। ■



ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 'ਰੇਡ ਰਾਜ'



- ਵੈਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੰਗ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗਲ

ਵੈਟ ਯਾਨੀ 'ਵੈਲਯੂ ਐਡਡ ਟੈਕਸ' ਜਾਂ 'ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਿਤ ਕਰ'। ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਰੇਡ-ਰਾਜ" ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਕਲਨ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹੈ। ਵੈਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 105 ਵਾਰਡ ਅਤੇ 10 ਜੋਨ ਹਨ। ਦੋ ਜੋਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੀਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਨੇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ

ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਛਗਿਛ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇ ਕਾਇਦਗੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੈਅ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ

ਵੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪੋਰਟੇਡ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਈਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਵੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਐਲਈਡੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਯਾਤਿਤ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ



ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਰਮ ਜੀ ਐਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਿਤ ਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2004 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2004 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੰਪਲੇਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਲ ਬਨਵਾਓ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਿਲ ਬਨਵਾਓ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿਲ ਜਰੂਰ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬਿਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਦੋਸ਼ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਉਗਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਬਨਵਾਓ-ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਗੁਜਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਗਮ-2 ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਦਮਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਿਥੇ ਵੇ ਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸੰਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਨਫਾਰਮਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ■



ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਮਾਪਤ



ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗਲ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮੇ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੇਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਬਨੇਟ ਨੇ ਸੇਲਫ ਅਟੇਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਭਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ, ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ, ਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਲਿਆਣ, ਐਮਸੀਡੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੇਂਸ਼ਨ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੇਂਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਐਸ ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ 40 ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਗਾ ਉਥੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹੁਗਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਸੇਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਸੇਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

- ▶ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ
- ▶ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ▶ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਨੇਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
- ▶ ਪਤਾ ਬਦਲਣ
- ▶ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਉਣ
- ▶ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਮਿਟ
- ▶ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ
- ▶ ਰੈਗੂਲਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ
- ▶ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਰਿਨਯੂਵਲ
- ▶ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ
- ▶ ਦਿੱਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ
- ▶ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ
- ▶ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ▶ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ▶ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
- ▶ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਾਤ ਘਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸੀ ਰੇਖਾ ਖਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਿਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਮਟਿਯਾ ਮਹਿਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸਿਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ, ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਛੇ ਲਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਲਟਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਤਰਾਜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।



ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤਾਹੀਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਲ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਟਵੀਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਦਿੱਲੀ)-ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਾਏਗਾ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੋਰਨਾਕਰ-(ਗੁਵਾਹਾਟੀ) ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੌਰਵ (ਪਟਨਾ) ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਰਿਸ਼ਲ ਅਰੁਣ (ਮੁੰਬਈ) ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਤਲਵਾਰ (ਦਿੱਲੀ) ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵਾਜ ਮੁਹੰਮਦ (ਕੁਵੈਤ) ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਨੀ ਪਾਲਥੇਪੁ (ਕਰੀਮਨਗਰ)- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿਸਣ ਲਗੇ ਹਨ।

ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ।

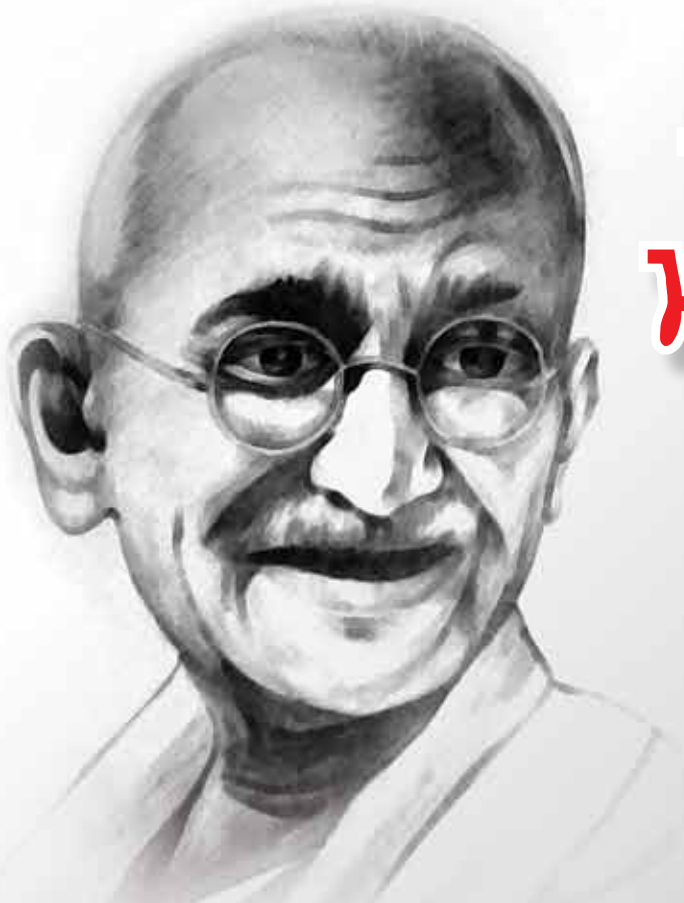
ਨੰਦਨ ਕੋਰੰਗਾ (ਦਿੱਲੀ) ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਏਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਸ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਿਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਲਤੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸ਼ਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੇਹਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ■



ਗਊ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢਾ ਬਣੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਲਿਸਤ ਭਰ ਨਮੂਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਭਰ ਨਮੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਮੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਮਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏਗਾ।

ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਊ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਗਊ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ।

ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।

ਤਦ ਕੀ ਗਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ? ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗਊ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦਯਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਊਕਸ਼ੀ ਵਧੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਯ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਨੀ ਸਭਾ ਗਊ ਵਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਨੀ ਸਭਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।

ਜਦ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਗਏ ਤਦ ਐਸੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵਾਂਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ ਤੋਂ) ■



ٹویٹر پر کچھ رد عمل

نویں پر کاش (دہلی) - کاش سارے لیڈر اردن کی طرح سچے اور ایماندار ہو جائے۔ میرا ملک پھر سے سونے کی چڑیا کہلائے گی۔

امیتا بھ بور تھاکر (گوہاٹی) - یہ آسام کے وزیر اعلیٰ کے لئے ایک نظیر ہے۔ انہیں بھی ایسے ایکشن لینے چاہیے۔

ابیشیک گورو (پٹنہ) - اسے کہتے ہیں بے حد ماضی سیاست

کریسل اردن (ممبئی) - ہمیں آپ پر فخر ہے اردن کچری وال

راجیش تلوار (دہلی) - وزیر اعلیٰ نے بہت صحیح قدم اٹھایا۔ یہ دو سرے سیاسی لیڈروں کے لئے ایک سبق ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے اور لیڈروں کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہئے۔

نواز محمد (کویت) - ہمیں اردن کچری وال پر فخر ہے۔ ہندوستان کی روح کو بچانے کے لئے آپ کو مرکز میں آنا ہوگا۔

شرینی پال تھیو (کشمیر) - سیاسی بدعنوانی پر لگام لگانے کے لئے کچھ امید رکھی ہے۔ نئے تصویر دیکھنے لگے ہیں۔

وویک بھارتی (بنگلورو) - عام آدمی پارٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بدعنوانی کو لے کر کافی سخت ہے۔

نندن کورنگا (دہلی) - میڈیا کو کچری وال کے اچھے کام کیوں نہیں دیکھتے؟ جو بہت غلط ہے۔ میڈیا نے دہلی سرکار کا کوئی بھی ایک اچھا کام کبھی بھی نہیں دکھایا۔

اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی گئی۔ کئی افسران اور ملازمین رشوت لیتے رنگے ہاتھ پکڑے گئے، لیکن جلد ہی مرکزی سرکار کے ساتھ حقوق کا جدوجہد شروع ہو گئی۔ مرکزی سرکار نے دہلی پولیس کی انٹی کرپشن برانچ (سی بی آئی) کو دہلی سرکار کے اختیار سے باہر بتا دیا۔ اس نے دہلی سے کار کے مہم میں بڑی رکاوٹ ڈالی۔

وزیر اعلیٰ اردن کچری وال اتنے پر ہی نہیں رُکے۔ انہوں نے 9 اکتوبر کو عاصم احمد خان کو وزیر کے عہدہ سے برخواستہ کرنے کے بعد 11 اکتوبر کو اپنے گھر پر پارٹی کے ایم ایل اے کی ایک بیٹھک بلائی۔ اس بیٹھک میں ایم ایل اے کے اہل خانہ کی ایک مٹینگ بلائی۔ اس مٹینگ میں ایم ایل اے کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے صاف طور پر کہا کہ بدعنوانی کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کرتی ہے۔ اگر کوئی بدعنوانی کرے گا تو سرکار کے ساتھ ساتھ پارٹی اور اس کے کنبہ کی بھی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے ایم ایل اے کے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی پارٹی ملک بدلنے کی ایک مہم ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کا شخص ایم ایل اے یا وزیر ہے تو اس کی شان کو بنائے رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ملک کو عام پارٹی کی سرکار سے بہت امیدیں ہیں۔ جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ ہم سیاست میں کیوں آئے ہیں۔

اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بھی پُر خلوص اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط کام کرنے والے کو سوجنا چاہئے کہ اگر وہ جیل گیا تو اس کے بچوں اور اہل خانہ کے لوگوں کو سماج میں کیا سننا پڑے گا۔ غلطی ایک آدمی کرتا لیکن بھگتنا پورے پر یوار کو پڑتا ہے۔ عام آدمی پارٹی انتظامی تبدیلی کے لئے بنی ہے اس امید کو سبھی کو پورا کرنا چاہئے۔

اردن کچری وال سرکار کے اس رخ کا دہلی کی عوام پر بے حد موثر اثر پڑا۔ لوگوں میں پیغام گیا کہ اردن کچری وال بدعنوانی کے خلاف جنگ کے اپنے وعدے کو بھولے نہیں ہیں نہ ہی وزیروں اور ایم ایل اے کو بھولنے دے رہے ہیں۔ اس کا سیدھا فائدہ عوام کو ہوگا کیوں کہ بدعنوانی سے پاک صاف حکومت ہی اصل میں اچھی حکمرانی ہوتی ہے۔

سنگین الزام پر اپنے ہی وزیر کو برخاست کیا کیجری وال نے سی بی آئی جانچ کی بھی سفارش

دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کجری وال نے بدعنوانی کے خلاف اپنی جنگ میں ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے جو مرکز اور ریاستی سرکاروں کے لئے چیلنج بن گئی ہے۔ کجری وال نے بدعنوانی کا الزام لگانے پر اپنے ہی ایک وزیر کو برخاست

جڑے اہم خلاصہ کرتا ہے۔ اسٹینک یا دستاویز عام کرتا ہے تو سیاسی جماعت الٹا حقائق کو توڑنے - مروڑنے کا الزام لگاتے ہوئے عدالت کے فیصلے کے انتظار کی دہائی دیتے ہیں۔ ایسے میں اروند کجری وال کا یہ قدم باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا رخ بدلنے پر مجبور کرے گا۔ عام آدمی پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں دہلی کے عوام سے ایک صاف - ستھری حکمرانی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دہلی کے عوام نے بدعنوانی کے خلاف حقیر مفاہمت جدوجہد کے اروند کجری وال کے وعدے پر نہ



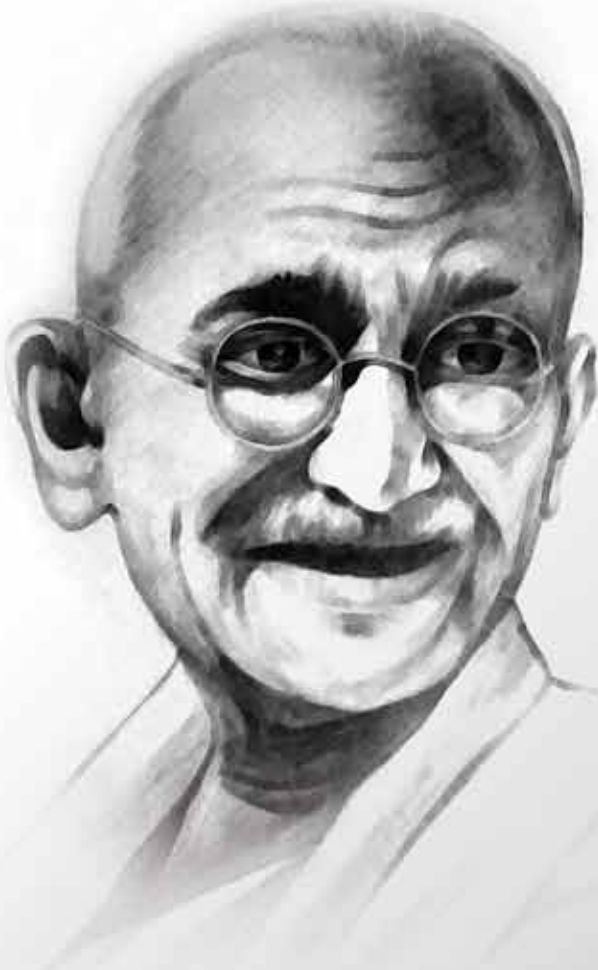
کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی سفارش بھی کر دی۔

برخاست کئے گئے وزیر کا نام عاصم احمد خان، ٹیما محل علاقے سے ایم ایل اے عاصم کے پاس دہلی سرکار کے خوارک و رسد کے علاوہ، ماحولیات و جنگلات، اقلیتی طبقہ معاملہ، اور محکمہ الیکشن بھی تھا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بلڈر سے چھ لاکھ روپے رشوت مانگی۔ اس بات چیت کی آڈیو ریکارڈنگ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کے پاس پہونچی انہوں نے وزیر سے صفائی مانگی اور انہیں بنا دیری کئے برخاست کر دیا

گیا۔ یہی نہیں انہوں نے خود پریس کانفرنس بلا کر میڈیا کو اپنے اس فیصلے کی جانکاری دی۔ 67 سیٹیں جیت کر عام آدمی پارٹی نے تاریخ قائم کر دیا۔

وزیر اعلیٰ اروند کجری وال کا یہ قدم سیاست میں ایک نئی مثال مانا جا رہا ہے۔ ابھی تک سیاسی جماعتوں میں عام متفق ہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے یہی اروند کجری وال نے بدعنوانی کے خلاف اپنی مہم شروع کر دی تھی۔

خانے کی حفاظت پر مہاتما گاندھی کی رائے



میں خود گائے کو پوجتا ہوں یعنی مان دیتا ہوں۔ گائے ہندوستان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کیوں کہ اس کی اولاد پر ہندوستان کو، جو کھیتی والا بڑا ملک ہے، انحصار ہے۔ گائے کئی طرح سے کارآمد جانور ہے۔ وہ مفید مطلب جانور ہے اسے مسلمان بھائی قبول کریں گے۔ لیکن جیسے میں گائے کو پوجتا ہوں، ویسے میں آدمی کو بھی پوجتا ہوں۔ جیسے گائے کارآمد ہے ویسے ہی آدمی بھی، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو کارآمد ہے۔

ہاں اور نہیں کے بیچ ہمیشہ دشمنی رہتی ہے۔ اگر میں بحث و مباحثہ کروں گا تو مسلمان بھی بحث و مباحثہ کرے گا۔ اگر میں ٹیڑھا بنوں گا، تو وہ بھی ٹیڑھا بنے گا۔ اگر میں بالشت بھر نموں گا تو وہ بھی ہاتھ بھرنے گا اور اگر نہیں بھی نئے تو میرا نمنا غلط نہیں کہلائے گا۔

جب ہم نے ضد کی تو گائے ذبیحہ بڑھی۔ میری رائے ہے کہ گائے کی حفاظت کی تبلیغ کرنے والی سبھا، گائے قتل تبلیغ کرنے والی سبھا مانی جانی چاہیے۔ ایسی سبھا کا ہونا ہمارے لئے بدنامی کی بات ہے۔

جب گائے کی حفاظت کرنا ہم بھول گئے تب ایسی سبھا کی ضرورت پڑی ہوگی۔

میرا بھائی گائے کو مارنے دوڑے تو اس کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کروں گا؟ اسے ماروں گا یا اس کے پیروں میں پڑوں گا؟ اگر آپ کہیں کہ مجھے اس کے پاؤں پڑنا چاہیے تو مسلمان بھائی کے پاؤں بھی پڑنا چاہیے۔

■ (’ہند سراج‘ سے)

تب کیا گائے کو بچانے کے لئے میں مسلمان سے لڑوں گا؟ کیا میں اسے ماروں گا؟ ایسا کرنے سے میں مسلمان اور گائے دونوں کا دشمن ہو جاؤں گا۔ اس لئے میں کہوں گا کہ گائے کی حفاظت کرنے کا ایک ہی تدبیر ہے کہ مجھے مسلمان بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہئے اور اسے ملک کے خاطر گائے کو بچانے کے لئے سمجھانا چاہئے۔ اگر وہ نہ سمجھے تو مجھے گائے کو مرنے دینا چاہئے کیوں کہ وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے گائے پر انتہائی رحم آتی ہے تو اپنی جان دے دینی چاہئے لیکن مسلمان کی جان نہیں لینی چاہئے۔ یہی مذہبی قانون ہے۔ ایسا میں مانتا ہوں۔



ایفی ڈیویٹ ختم

دنوں میں اس تعداد کو اور کم کیا جائیگا۔ جہاں بید ضروری ہوگا وہیں حلف نامہ مانگا جائے گا۔ بہر حال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار جھوٹ سیلف ڈکلیریشن دینے والوں کے تحت لا پرواہ رہے گی ایسا کرنیوالوں کو سخت سزا دلانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔

صرف سیلف ڈکلیریشن سے ہوگا کام۔

- داخلے کے وقت دئے جانے والے ایفی ڈیویٹ ڈیف آف برتھ، اسکول سے گھر کی دوری
- نوکری کی شروعات میں سرٹی فکٹ کی حقائق کیلئے دئے جانے والا حلف نامہ
- نام اور سر نام میں تبدیلی کیلئے دئے جانے والا حلف نامہ
- پتہ بدلنے
- راشن کارڈ بنوانے اور اس میں ضروری تبدیلی کرنے
- پرمٹ ٹرانسفر کرانے
- ڈپلیکٹ آر سی
- ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے۔
- ڈرائیونگ لائسنس کا رینول
- انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ۔
- دہلی لاڈلی اسکیم۔
- پیدائش و موت سرٹی فکٹ کے ریکارڈ میں تبدیلی
- باشندہ سرٹی فکٹ۔
- آمدنی سرٹی فکٹ
- او بی سی، ایس سی، ایس ٹی، سرٹی فکٹ
- نیا بجلی کنکشن کے وقت دئے جانے والا حلف نامہ
- کمیونٹی سینٹر، بارات گھر یا پارک بکنگ کے وقت دینے والا حلف نامہ ■

عوام کی بات پر بھروسہ کر کے اس سے ہر بات کیلئے حلف نامہ مانگا جائے۔ اب دہلی میں ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں پر پورا اعتماد جتاتے ہوئے دہلی سرکار نے ایک اہم فیصلے میں الگ الگ درجوں قریب 200 کاموں کیلئے حلف نامے (ایفی ڈیویٹ) کی لازمی کو ختم کر دی ہے۔ اس کے بدلے سیلف ڈکلیریشن ہی کافی ہوگا۔ ساتھ ہی کابینہ نے سیلف اسٹیشن کو بھی منظوری دیدی ہے۔ یعنی لوگ اپنے تصدیق نامہ کو خود ٹیسٹ کر سکیں گے۔ انہیں کسی صوبے کے سرکاری افسروں کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ یکم دسمبر سے لاگو ہوئے اس نظم و نسق کے ذریعہ دہلی سرکار نے عوام سے کیا گیا اپنا ایک اہم وعدہ پورا کر دیا ہے۔

نائب وزیر اعلیٰ منیس سسودیا کے مطابق 200 قسم کے کاموں میں ایفی ڈیویٹ ختم کرنے کے فیصلے کا اثر سرکار کے ایسے تمام محکموں کی کارکردگی پر پڑے گا جہاں عوام کو اکثر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ سرکار نے تمام محکموں سے ایسے حلف ناموں کی جانکاری مانگی تھی جنہیں جمع کرنا لازمی تو تھا لیکن یہ محض رسمیت تھی۔ ایجوکیشن محکمہ، محکمہ محصول، ٹرانسپورٹ محکمہ، محکمہ صارفین خوراک و رسد، رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، سماج کلیان محکمہ، زچہ و بچہ کلیان بہبود، ایم، سی ڈی، رجسٹرار پیدائش و موت جیسے محکموں میں کوئی حلف نامہ نہیں دینا ہوگا۔

نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اب راشن کارڈ بنانے، اور اس میں نام جوڑنے یا گھٹانے، ڈپلیکٹ راشن کارڈ، پتہ میں تبدیلی، گاڑیوں کے رجسٹریشن، ڈرائیونگ لائسنس، دہلی لاڈلی اسکیم، بیوہ پنشن، معذور پنشن، آمدنی سرٹی فکٹ، او بی سی، اور ایس سی ایس ٹی سرٹی فکٹ بنوانے کیلئے کسی ایڈوکیٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فی الحال 40 کاموں میں حلف نامہ کی نظم جاری رہے گی لیکن آنے والے

بل بنواؤ - انعام پاؤ

دہلی سرکار نے ”بل بنواؤ انعام“ نام سے نئی اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم کے تحت لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جو بھی سامان خریدیں اس کی پکا بل ضرور لیں۔ سرکار نے اس بابت 50 ہزار روپے تک انعام رکھا ہے اس کیلئے خریدی گئی چیزوں کی قیمت 100 روپے سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ اس کے بعد بل کی کاپی کو محکمہ کی ویب سائٹ پر 7 دنوں کے اندر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ہر ایک بل کیلئے یونیک آئی ڈی نمبر جاری کیا جائے گا اور ایس ایم ایس کے ذریعہ صارفین کو بھیج دیا جائے گا۔ کچر یوال سرکار نے اعلان کیا ہے کہ ہر ایک مہینے انعام دیا جائیگا۔ صارفین کے دباؤ پکی رسید دینے کا دباؤ دکانداروں پر بڑھے گا جس سے سرکار کو زیادہ ٹیکس مل سکے گا۔

سے صاف ہو جائے کہ تاجر نے کہاں سے مال مانگایا، کہاں بیچا اور کتنا منافع کمایا۔ اگر سب کچھ شفاف ہو جائے تو پھر ویٹ چوری یا تنازعہ کی شک پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ انعام پانے والے تاجروں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور سرکار کو بھی ویٹ چوری کی پریشانی سے نہیں جو جھنا پڑے گا

یہی نہیں، سرکار میں ایک انفارمر اسکیم بھی شروع کی ہے۔ اس کے تحت ویٹ چوری کی اطلاع دینے کیلئے لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے۔ اطلاع دینے والے کی پہچان پوشیدہ رکھا جائے گا اور اگر اطلاع کی وجہ سے ویٹ وصولی ہو پائی تو مناسب انعام دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ویٹ افسروں اور ملازمین کا حوصلہ بڑھانے کی بھی یوجنٹ لائی جا رہی ہے۔

کے وہ تاجروں سے پوری سنجید سے پوچھتا چھ کریں۔ اس کے برتاؤ سے کسی کی عظمت کو ٹھیس نہ پہونچے اس کا خاص دھیان رکھا جائے۔ ضابطہ کے تحت 100 روپے سے زیادہ قیمت کے چیزوں کی فروختگی پر پکی رسید دینا ضروری ہے۔ لیکن اس ضابطہ کی تعمیل نہ کرنے کی شکایت بڑے پیمانے پر ہے۔ ایسے میں صارفین کو پکی رسیدیں لینے کے لئے حوصلہ مند کیا جا رہا ہے۔ اس کے لئے بل بنواؤ اسکیم شروع کی گئی ہے۔

اس کے ساتھ دہلی میں باہر آنے اور یہاں سے گزر کر جانے والے مال کا حساب کتاب رکھنا لازمی کر دیا گیا ہے۔ اس کے لئے آسان-2 فارم کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ کاپی راست فارم ہے اس سے مرکزی پیداوار محکمہ اور انکم ٹیکس کو بھی جوڑنے کی تکنیک اپنائی جا رہی ہے۔ تاکہ یہ پوری طرح



طلب کیا جاتا ہے۔ ضروری ہونے پر سروے کیا جاتا ہے اور ساری پوچھ تاچھ دستاویزوں کے بنیاد پر ہوتی ہے اس سروے کی پوری ویڈیو گرافی کرائی جاتی ہے۔ تاکہ کس طرح بے ضابطگیوں یا دباؤ کی شکایت کی گنجائش نہ رہے۔ ساتھ ہی ویٹ کمشنر آخری وقت پر طے کرتے ہیں کہ کون کون سے آفس سروے کرنے کرنے کیلئے مشتبہ تاجروں کے تنصیبات پر جائیں گے۔ یعنی کسی افسر کا طے شدہ علاقہ نہیں ہے۔ پہلے کے انتظام میں ویٹ ملازمین کے طے وارڈ یا علاقہ ہوتے تھے اور یہ نظام عام تھا کہ وہ تاجروں سے باقاعدہ وصولی کرتے ہیں نئی سرکار نے ویٹ افسروں اور ملازمین کو واضح ہدایت دی ہے۔

دہلی میں 105 وارڈ اور 10 زون ہیں۔ دوزون ایسے بھی ہیں کہ جو خاص ایک کروڑ سے زیادہ ریٹرن دیتے ہیں۔ دہلی میں قریب تین لاکھ رجسٹرڈ ڈیلر ہیں۔ جن بھی تاجروں کا سالانہ ٹرن اوور ہے ان کا ویٹ محکمہ میں رجسٹریشن لازمی ہے۔ لیکن سرکار تاجروں کو راحت دینے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو لیکر بھی کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے تحت بزنس اعلیٰ جنس یونٹ کی تشکیل کی گئی ہے۔ ان میں ویٹ آفیسروں کے علاوہ ٹیکس ماہرین بھی ہیں۔ جو محکمہ میں تاجروں سے ملے اعداد و شمار کا غور و فکر کرتے ہیں اگر کوئی نقص پائی جاتی ہے تو مشتبہ تاجروں سے جواب

ٹ محکمہ نے قروں باغ کی ایک فرم کے قریب 50 کروڑ روپے کے مہنگے ایمپورٹریڈ ایل ای ڈی ٹی وی سیٹ کا اسٹاک ضبط کیا۔ ان ایل ای ڈی ٹی وی کو غیر قانونی سے بیچا جا رہا تھا ایل ای ڈی ٹی بیچنے والی فرم ابھی تک ویٹ محکمہ میں رجسٹرڈ بھی نہیں تھی۔

زیادہ کی ٹیکس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ ٹیکس چوری کرنے کے پاس ایل ای ڈی کا بھر مار اسٹاک پایا گیا۔ اطلاع کی کرنے کے طور طریقوں کو بھی دیکھا۔ پوری تیاری کے



ٹ کمشنر ایس ایس یادو نے بتایا کہ 10 کروڑ روپے سے ب کے خلاف مہم میں اور تیزی لائی جائے گی۔ اس فرم پر ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ایریا کا سروے کیا اور فرم کے کام چھاپے ماری کی گئی۔

پوری اسٹاف کو درآمد کیا گیا تھا جس فرم سے ایل ای ڈی سے ان ٹی وی سیٹوں کی فروخت کی کر رہا تھا۔ ویپا پار اور ٹیکس پیمانے پر درآمد شدہ ایل ای ڈی ٹی وی بیچ رہی ہے کوئی

ٹ کمشنر نے بتایا کہ فرم کے ذریعہ ایل ای ڈی ٹی وی کے ای کا اسٹاک ضبط کیا گیا، وہ قروں باغ میں غیر قانونی طور رٹمنٹ کو اطلاع ملی تھی کہ قروں باغ کی ایک فرم بڑی

ن نہیں دیا جا رہا ہے۔ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد انفورسمنٹ ٹیم نے فرم پر چھاپہ مارا۔ فرم جی ایس اوور سیز کے پاس ان ٹی سیٹوں کا بڑی اد میں اسٹاک پایا گیا۔ کمپنی کے مالک نے غیر قانونی طریقے سے ٹی وی بیچنے کی بات مان لی ہے۔ ان افسروں نے لین دین سے جڑی سبھی ضروری ناویز بھی ضبط کئے ہیں۔ ویٹ کمشنر کے مطابق اس فرم نے کسی بھی ٹیکس کی ادائیگی نہیں کیا ہے۔ دہلی ترمیم شدہ ٹیکس قانون 2004 کے مطابق کسی بھی شخص رم کا سالانہ کاروبار 20 لاکھ روپے سے زیادہ ہونے پر اسے ویپا پار اور ٹیکس محکمہ میں رجسٹریشن کروانا چاہئے۔ اسے ایک ٹن نمبر ملتا ہے اور ریٹرن فائل اجاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے DVAT قانون 2004 کے مطابق فرم کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پوری شکایت بھی فائل کی گئی ہے۔ اس پیشن میں جوائنٹ کمشنر رنجیت سنگھ اور اسسٹنٹ کمشنر وکاس تو مر بھی شامل تھے۔

ٹ کمشنر نے کہا کہ قاعدہ قانون ماننے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ٹیکس چوروں کو بخش نہیں جائیگا۔

دہلی میں ختم ہوا 'ریڈ راج'



- ویٹ محکمہ کے بدلے رنگ
- بدعنوانی سے پاک شفاف ٹیکس انتظام نافذ
- تاجروں سے وصولی ہوئی گزریے زمانے کی بات

دہلی کے کچر یوال سرکار نے اس حیثیت کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ 'ریڈ راج' بند کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ تاجروں پر پوری طرح بدل دیا ہے۔ سرکار نے 'ریڈ راج' بند کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ تاجروں پر پوری طرح اعتماد کرتی ہے یعنی آئے دن تاجروں پر ہونے والی غیر معقول چھاپے ماری پوری طرح بند کر دی گئی تاجر اپنے ٹیکس کا تخمینہ خود کرتے ہیں۔ اور ریٹرن کو آن لائن بھرا جاتا ہے۔ جسے سرکار پوری طرح منظور کرتی ہے۔ ساتھ ان کی شکایتوں کے پٹارے کیلئے شفاف نظام قائم کی گئی۔ ویٹ کے لحاظ سے

ویٹ یعنی 'ویلیو ایڈیڈ ٹیکس' یا قیمت ترقی ٹیکس۔ تاجروں کے کارکردگی کے حوالے میں وصولے گئے اس ٹیکس سے سرکار ترقی کے تمام کام کراتی ہے۔ لیکن اس ٹیکس کو لیکر سرکار اور تاجروں کے بیچ لگا تارتا و بنا رہتا تھا۔ محکمہ ویٹ کی جانب سے آئے دن چھاپے ماری اور غیر قانونی وصولی کی شکایت تاجر کرتے تھے تو دوسری طرف ان پر ٹیکس چوری کا الزام بھی لگتا تھا۔ ہر طرف عدم اعتمادی کا ماحول تھا۔

‘کارفری ڈے’ سے آلودگی میں 60 فیصدی کمی !

دہلی میں جہاں ‘کارفری ڈے’ منایا گیا ہے وہاں آلودگی میں 60 فیصدی کمی آئی۔ دہلی میں 73 لاکھ گاڑیاں روزانہ سڑکوں پر اترتی رہیں اگر انہیں ایک دن کے لئے بھی روکا گیا تو 216 کروڑ لیٹر ایندھن کی بچت کی جاسکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں 8.58 ٹن باریک ریزہ 7.4 ٹن سلفر ڈائیوکسائیڈ، 105.38 ٹن نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور 452.51 ٹن کاربن مونو آکسائیڈ کو بھی ہوا میں گھلنے سے روکا جاسکتا ہے۔

ایک ارب سے زیادہ کاریں دنیا بھر میں ہیں ہر کار ایک کلومیٹر میں 48 گرام باریک ریزہ اور 30 گرام سلفر ڈائی آکسائیڈ چھوڑتی ہے پوری دنیا میں اس خطرے کو محسوس کیا جا رہا ہے کولمبیا کے بگوٹا میں 15 سال پہلے شروع ہوا ‘کارفری ڈے’ اب دنیا بھر کے شہروں میں منایا جانے لگا ہے۔ عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 20 سب سے آلودہ شہروں میں سے 13 بھارت کے ہیں۔ آلودگی کا خاص سرچشمہ گاڑیاں ہی ہیں۔ ایسے میں اگر ان گاڑیوں کے پھیے ایک دن بھی روک دیئے جائیں تو آلودگی میں بھاری کمی دیکھی جاسکتی ہے۔

سرکار کی تیاریاں ماحولیات کی حالت کی سنجیدگی کا پتہ دے رہی ہے۔ ایسے میں سوال دہلی والوں سے ہے کہ وہ کتنی طاقت سے یہ کہنے کو تیار ہیں۔ ”آؤ اب بس کریں“

سہولیت اور حفاظت کے ساتھ دہلی کے لوگ آمد و رفت کرسکیں۔ اس کیلئے سرکار ہر ممکن کر رہی ہے۔



دیا تھا۔ تاجر بھی دوسرے شہروں میں ہجرت کر رہے تھے آخر کا اس کے خلاف عوام نے آواز بلند کی۔ ماحولیات سیاسی دلوں کو مدعی بنا۔ گرین پارٹی وجود میں آئی اور آج یہ شہر یورپ کے سب سے خوبصورت شہروں میں مانا جاتا ہے۔

وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق ایسے میں دہلی کی حالت سدھانے کیلئے بھی جن جاگرن سب سے ضروری ہے۔ تمام لوگوں کیلئے کاریں دکھا دوے کا ذریعہ ہے۔ ایک ایک گھر میں کئی کاریں ہیں۔ اس کو ذہنی طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ گاڑیوں کا استعمال کریں۔ جہاں تک ہوسیک سائیکلوں کا استعمال کریں۔ تبھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ”آؤ اب بس کریں“ مہم کا یہی مقصد ہے کہ لوگ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور بس یا دوسرے عوامی گاریوں کا استعمال میں زیادہ دلچسپی لیں۔

لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا دہلی کے لوگوں کو محفوظ آرام دہ عوامی گاڑیوں کا انتظام موجود ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں گوپال رائے سرکار کے عہدہ ہراتے ہیں۔ ان کے مطابق میٹرو کے تیسرے دور کے توسیع کا کام زوروں پر ہے۔ اس کے علاوہ دہلی اینٹی گریڈ ملٹی ماڈل ٹرانزٹ سسٹم (ڈٹس) اور ڈی ٹی سی کے تحت ایک ہزار نئی بسیں خریدی جارہی ہیں۔ پانچ نئے ڈپو بنائے جارہے ہیں۔ سرکار کی کوشش ہے کہ اچھی ایئر کنڈیشن بسین سڑکوں پر چلیں تاکہ دہلی والوں کو نجی گاڑیوں سے نہ چلنے کا افسوس نہ ہو۔

وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق اگلے سال تک پانچ ہزار نئی بسوں کا بیڑہ دہلی کی عوامی نقل و حمل کے نظم کو کافی بہتر بنائے گا۔ کوشش ہوگی کہ لوگوں کو اپنے گھر سے مقام تک پہنچنے کے لئے ہر سطح کی سہولت ملے۔ ای رکشا اور فیڈر بسوں کے ذریعہ میٹرو تک پہنچنے کا آسان انتظام لوگوں کو جاذب کرے گا۔

گوپال رائے کے مطابق اب تک 1300 بسوں میں مارشل کا تعیناتی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسی مالی سال میں سول ڈیفنس سے پانچ ہزار اور حفاظتی ملازمین کی تعیناتی کی جائے گی۔ ساتھ ہی پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 10 بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جارہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد سبھی بسوں میں اس کا فروغ ہوگا۔



وزیر ٹرانسپورٹ گوپال رائے کے مطابق اب ہر مہینے کی 22 تاریخ کو دہلی کی الگ الگ علاقوں میں کارفرمی ڈے منایا جائیگا اور اگلے سال 23 ستمبر کو پوری دہلی کارفرمی ڈے منائیں گے۔ اسی دن عالمی سطح پر کارفرمی ڈے کا انعقاد ہوتا ہے۔ نتیجے بتاتے ہیں کہ جس راستے پر کارفرمی ڈے منایا جاتا ہے وہاں آلودگی میں کافی کمی آتی ہے۔

ایک اندازے کے مطابق دہلی میں لگ بھگ 90 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پڑوسی ریاستوں سے بھی گاڑیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ کوکاتہ، ممبئی اور چنئی میں کل ملا کر چنئی گاڑیوں ہیں اس سے زیادہ اکیلے دہلی میں ہیں۔ ان گاڑیوں سے نکلنے والی دھوئیں میں جو نقصان دہ عناصر ہیں وہ ماحولیات سدھار کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی چوراہے پر جام لگا رہتا ہے جو آلودگی کی سطح کو اور خطرناک بنا دیتا ہے۔

وزیر ٹرانسپورٹ گوپال رائے کے حال ہی میں ایک معلوماتی پروگرام کے تحت سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم گئے تھے۔ یہ شہر آلودگی بربادی اور پھر آئے سدھار کا سب سے بڑا نظیر ہے۔ گوپال رائے کے مطابق 70-1960 کے دمشق میں اسٹاک ہوم کی حالت بھی کچھ۔ کچھ دہلی کی طرح ہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس شہر میں رہنا خطرناک اعلامیہ کر



دہلی کو بچانا ہے تو

آؤ اب بس کریں

اس راستے پر لوگوں نے سائیکل ریلی نکالی جس میں خود وزیر اعلیٰ اروند کچر یوال شامل ہوئے۔ کچر یوال نے لال قلعہ سے بھگوان داس مارگ تک سائیکل چلائی اور حصہ لینے والوں سے اپیل کی وہ سائیکل چلانے کو ایک عادت بنائیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پرسنل گاڑیوں چھوڑ کر عوامی گاڑیوں کا استعمال کرنا چاہئے۔ دہلی میں آلودگی برہم رہی ہے۔ ایسے میں سائیکل چلانے کی ضرورت ہے۔ جو صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ذیابیطیس سے دکھی ہیں اور سائیکل چلانے سے اس کے صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے دہلی کی سڑکوں کو محفوظ بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ ان کی سرکار انہیں پھر سے ڈیزائن کرنے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے۔

دہلی میں آلودگی کی پریشانی لگاتار گہراتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گاڑیوں سے نکلنے والا خطرناک دھواں، میٹرو کے پھیلاؤ کے باوجود سڑکوں پر گاڑیوں کی بوجھ کم نہیں ہوا ہے۔ سی این جی سے جو راحت ملی تھی اسے گاڑیوں کی تیزی سے بڑی تعداد نے بیکار کر دیا۔ ایسے میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ نجی گاڑیوں کو چھوڑ کر گورنمنٹ گاڑیوں کا استعمال کریں۔ ساتھ ہی سائیکلوں کے استعمال پر زور دیا جائے۔ حالات کی دوراندیشی کو سمجھتے ہوئے دہلی سرکار نے 'آؤ اب بس کریں' مہم کی شروعات کی ہے۔ اس کے تحت پہلا کارفری ڈے 22 اکتوبر کو منایا گیا جب لال قلعہ سے لیکرانڈیا گیٹ کے بیچ ایک طے شدہ راستے پر کاروں یا دیگر گاڑیوں کے چلنے پر پابندی تھی۔

اور پھر سپر اسپیشلیٹی گنجائش والے اسپتال۔ اونچی سطح جانچوں کے لئے دہلی میں 100 پالی کلینک بھی کھولے جانے ہیں۔ یہ محلہ کلینک اور بڑے اسپتالوں کے بیچ لنک کا کام کریں گے۔ 09 نومبر کو گاندھی نگر کے کانتی نگر میں وزیر اعلیٰ کچر وال نے پہلے پالی کلینک کا افتتاح کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس ماڈل کلینکوں کے کام کاج پر سخت نگرانی رکھی جائے گا تا کہ جب 100 پالی کلینک کھل جائیں گے تو دہلی والوں کو پورا فائدہ ملے سکے۔

وزیر صحت ستیندر جین کہتے ہیں کہ آزادی کے 68 سالوں کے بعد دہلی کے اسپتالوں میں محض 10 ہزار بیڈ کا انتظام ہے جن میں مریضوں کیلئے بمشکل ایک ہزار ہے۔ اگلے دو سے ڈھائی سال کے اندر سرکار اسپتالوں میں بیڈوں کی تعداد کو بڑھا کر بیس ہزار کر دے گی جس میں سات سے آٹھ ہزار ایمرجنسی اور آئی سی یو کیلئے استعمال ہونگے۔ ساتھ ہی سرکار دہلی میں 250 ڈسٹریکٹ کلینک بھی کھولنے جارہی ہے۔ جس سے لوگوں کو بڑی راحت ملے گی۔

سرکار نے صحتی خدمات کے لحاظ سے دہلی کو مشرقی، شمالی، مغربی، جنوبی اور سینٹرل زون میں بانٹا ہے۔ یہ پانچوں علاقہ صحت خدمات کی لحاظ سے خود منحصر ہونگے۔ یعنی محلہ کلینک، پالی کلینک اور سپر اسپیشلیٹی اسپتال کا پورا نظام ہر علاقہ میں موجود رہے۔ کسی کو دوسرے علاقہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ یعنی لوگوں کے وقت اور پیسہ کی بچت ہوگی۔ ■



اس سے مریضوں کو جانچ کرانے، رپورٹ لینے اور پھر اسے ڈاکٹروں کو دکھانے کے ترتیب میں جو وقت اور پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا وہ بھی بیچ رہا ہے۔ یعنی جب پوری دہلی میں ایک ہزار محلہ کلینک کھل جائیں گے تو بڑے اسپتالوں میں مریضوں کی بھیڑ نہیں دکھے گی۔ ابھی کئی اسپتالوں میں ریلوے پلیٹ فارم جیسے نظارے دکھتے ہیں کئی جگہ ایک بیڈ پر دو مریض بھی پڑے دکھتے ہیں لیکن مریض کو شروع میں ہی علاج ملے جائے گا تو زیادہ تر معاملوں میں بیماری بڑھنے ہی نہیں پائی گی۔

جناب جین نے بتایا کہ محلہ کلینک میں مریضوں کو ٹوکن دے دیا جائیگا تا کہ انھوں اپنی باری آنے کے وقت کا اندازہ ہو جائے اگلے مرحلہ میں ایک ایپ استعمال ہوگا جس سے لوگوں کو موبائیل کے ذریعہ اپوینٹمنٹ اور دیگر اطلاع ملے سکے۔ دراصل، دہلی سرکار کی یوجنا دہلی کو صحت کا تین سطحی سیکوریٹی مہیا کرانا ہے۔ پہلے مرحلہ میں محلہ کلینک، پھر پالی کلینک

دہلی والوں کو ملیں گے 'ہیلتھ کارڈ'

دہلی کے لوگوں کی صحت پر خاص دھیان دیتے ہوئے سرکار ہیلتھ کارڈ اسکیم پر کام کر رہی ہے۔ ارادہ اگلے سال - ڈیڑھ سال میں صحت خدمات کو آن لائن کرتے ہوئے ہر شہری کو ایک ہیلتھ کارڈ مہیا کرانا ہے۔ اس کارڈ میں مریض کی نئی اور پرانی

بیماریوں کا پوری حساب کتاب ہوگا۔ مریض محلہ کلینک، پالی کلینک اور سپر اسپیشلیٹی اسپتالوں میں ان استعمال کر سکے گا۔ اسے اپنی جانچ رپورٹ لیکر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبھی کچھ آن لائن ہوگا اور بائیو میٹرک ہیلتھ کارڈ کے ذریعہ ڈاکٹر مریض کی جانچ رپورٹ اور بیماریوں و استعمال کی گئی دواؤں کا اتھاس پلک جھپکتے جان لے گا۔



محله کلینک صحت کا اے ٹی ایم



کلینک کا نام دے رہے ہیں۔ یہاں مریضوں کو بیٹھنے کے لئے کرسیاں، پینے کا صاف پانی اور ٹیلی ویژن بھی ہیں۔ غریبوں کے لئے تو یہ کلینک ایک نعمت کی طرح ہے۔ کیونکہ بیمار پڑھنے پر انھیں جن جانچوں کے لئے دردر بھٹکنا پڑتا تھا وہ اب ان کے دروازے ممکن ہے۔ جانچ رپورٹ دیکھ کر جو ڈاکٹر دوا انھیں لکھتے ہیں وہ بھی اسی کلینک سے مل جاتی ہے۔

دہلی کے وزیر صحت جناب ستیندر جین کہتے ہیں کہ پہلے اندازہ تھا کہ 80 فیصدی مریضوں کو محلہ کلینک سے راحت مل جائے گی صرف 20 فیصدی کو ہی بڑے اسپتالوں میں بھیجنا پڑے گا لیکن تجربہ بتا رہا ہے کہ محلہ کلینک میں 95 فیصدی تک مریضوں کا علاج ممکن ہے۔ ابھی تک 50 طرح کے جانچ کی سہولیت کو مستقبل میں 100 کرنے کی اسکیم ہے۔

پہلے محلہ کلینک کی شروعات کے ساتھ ہی دہلی میں صحت کے درجے میں ایک نئے انقلاب کی شروعات ہو گئی ہے کچر وال سرکار اپنے وعدے کے مطابق پوری دہلی میں ایک سال کے اندر 1000 محلہ کلینک کھول دے گی۔ مطلب لوگوں کے محلے میں علاج اور جانچ کی سہولیت، بیماریوں کو پنپنے سے پہلے ہی پکڑنے اور ختم کرنے کی جانب میں محلہ کلینک اہم رول ادا کریں گے۔

آخر محلہ کلینک ہے کیا اور اس میں نیا کیا ہے؟ اس کی جھلک مغربی دہلی کے پیرا گڑھی کے علاقے میں کھلے پہلے محلہ کلینک سے ملتی ہے۔ اس پوری طرح انٹر کنڈیشن میں ڈاکٹر، نرس کے ساتھ فارمسٹ اور لیب ٹیکنیشن بھی ہیں۔ اور 50 سے زیادہ جانچ کی سہولت صرف 20 لاکھ روپے میں بنے اس کلینک کو لوگ فانیو اسٹار

دہلی کو پہلے ہی سال 245 نئے اسکولوں کا تحفہ !

سرکار نے پانچ سال میں 500 اسکول بنانے کا وعدہ کیا تھا

دہلی میں اسکولی ایجوکیشن کی حالت بدلتے کیلئے سرکار کی کوششوں کا اثر دکھانے لگا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بننے پر دہلی میں پانچ سال میں پانچ سو نئے اسکول بنائے جائیں گے۔ لیکن جس رفتار سے سرکار نے کام کیا اس سے لگتا ہے کہ ایک سال ہی میں اس کا آدھا مقصد پورا کر لیا جائے گا جو ایک مثال ہے۔

دہلی میں پرائمری سے لیکر درجہ 12 تک کل 1011 اسکول ہیں۔ گیارہویں اور بارہویں طلباء کی تعداد قریب تین لاکھ سے اوپر ہے۔ جب نئی سرکار کمان سنبھالی تو اساتذہ، طلباء تناسب میں بھاری اسنٹولن (ایک کلاس میں کہیں 174 تک طلباء تھے) سے لیکر کمروں کی بھاری کمی سامنے تھی۔ حالت بدلتے کیلئے بڑی سطح پر کوشش شروع ہوئی۔ سرکار نے اسکولی ایجوکیشن کی تصویر بدلنے کیلئے ٹھوس پروگرام شروع کئے۔ اس کے تحت کل 25 اسکول زیر تعمیر ہیں۔ اور اگلے ٹرم بھی 20 نئے اسکول بن جائیں گے۔ وزارت تعلیم کا کام کاج سنبھال رہے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے مطابق موجودہ

اساتذہ کی تعداد بڑھانے پر اساتذہ ہر طلباء پر دھیان دے پائے گا اور اساتذہ کی معیار میں سدھار آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسکولوں میں بیت الخلا سے لیکر لیبارٹریوں کی کمیوں کو پورا کرنے پر خاص زور دیا جا رہا ہے۔ ارادہ کہ سرکار اسکولوں میں پڑھنا اور پڑھانے بالکل نیا تجربہ ہو۔ ان اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے کسی بھی طرح نجی اسکولوں کے بچے سے کمتر نہ ثابت ہوں۔

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں

اسکولوں میں 8000 کمرے جوڑنے کی تجویز پاس ہو چکی ہے۔ اگر ایک اسکول اوسطاً 40 کمروں



دہلی جن لوک پال بل 2015 پاس



یعنی سال بھر میں معاملے کو انجام تک پہنچانا اس بل کی لازمی شرطیں ہیں۔ 18 نومبر کو دہلی سرکار کی کابینہ سے منظوری ملنے کے بعد دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے ٹویٹ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ انھوں نے اس ٹویٹ میں لکھا۔۔۔

”دہلی کے لئے یہ تاریخی لمحہ ہے۔ دہلی کابینہ نے جن لوک پال بل کو منظوری دی ہے۔ ان سبھی کو مبارکباد جنہوں نے اس کے لئے دن رات محنت کی۔“

دہلی جن لوک پال بل میں کرپشن کرنے والوں پر بھاری جرمانہ لگائے جانے کا بھی انتظام ہے۔ الزام ثابت ہونے پر پروپٹی ایجنٹ منٹ کا انتظام بھی اس بل کے تحت سے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی سرکار یہ یقینی بنائے گی کہ کورٹ بھی کافی تعداد میں ہو۔ زیادہ سے زیادہ کورٹ ہونگے تو مقررہ وقت رہتے میں ٹرائل پورا ہو سکے گا۔ ■

اروند کچر وال سرکار نے اپنا ایک بڑا وعدہ پورا کرتے ہوئے جن لوپال بل کابینہ سے پاس کر دیا، اس بل کے دائرے میں وزیر اعلیٰ دفتر کو بھی رکھا گیا ہے۔ اس کا نام دہلی جن لوک پال بل 2015 ہے۔

غور طلب ہے کہ بدعنوانی کے خلاف ہوئے زوردار اثا تحریک کی یہ اہم مانگ تھی جسے دہلی کے عوام نے زبردست حمایت دیا تھا۔ اس تحریک کے کوکھ سے عوام آدمی پارٹی کا جنم ہوا تھا جس نے اقتدار میں آنے پر جن لوک پال بل پاس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پچھلے بار اس بل کو پیش نہ کئے جانے پر اختلاف جتاتے ہوئے اروند کچر وال اور ان کی سرکار نے استعفیٰ دیا تھا۔ دوبارہ زبردست اکثریت کے ساتھ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے جن لوک پال قانون بنانے کی کارروائی تیز کر دی تھی۔

اس بل کے تحت کسی بھی جانچ کو چھ مہینے کے اندر پورا کرنا ہوگا۔ ٹرائل بھی چھ مہینے کے طے وقت میں پورے کرنے ہونگے۔

बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, मैरेज हॉल, होटल, पार्क इत्यादि के मालिकों / पट्टेदारों / संरक्षकों के लिए आवश्यक सूचना



- व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली में पंजीकरण अनिवार्य है।
- ऑन-लाइन बी ई-1 फार्म भर कर पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है।
- ऑन-लाइन बी ई-2 फार्म में पाक्षिक रिटर्न भरना भी अनिवार्य है।
- इसकी अवमानना मूल्य एवं संबंधित कर अधिनियम 2004 (DVAT, ACT-2004) के तहत अपराध है।
- स्थानीय निकाय / सरकारी विभागों के स्वामित्व / अधिकृत स्थलों के लिए भी यह अनिवार्य है।

अधिक जानकारी एवं अधिसूचना के लिए
वेबसाइट www.dvat.gov.in देखें

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

व्यापार एवं कर विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार

आप की सरकार



दिल्ली सरकार से कोई भी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब लाईन में लगाने या रिश्वत देने की जरूरत नहीं

पुराना सिस्टम	नया सिस्टम
सरकारी दफ्तरों में लम्बी लाईन	घर बैठे, 24x7 ऑनलाइन आवेदन
एफिडेविट बनवाने का चक्कर	जरूरत नहीं
MP/MLA या अफसर के अटेस्टेशन	जरूरत नहीं
प्रमाणपत्र के लिए महीनों का इंतज़ार	अधिकतम 2 सप्ताह
डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के लिए दोबारा आवेदन	जब चाहे वेबसाइट से प्रिंट ले लें
दलालों के रैकेट से फर्जी प्रमाणपत्र का ख़तरा	ऑनलाइन सिस्टम से दलालों का रैकेट ख़त्म

प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लॉग ऑन करें—

<http://edistrict.delhigovt.nic.in>

जो कहा सो किया



राजस्व विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार



DIP/Shabdarth/D0047/15-16